लखनऊ

शुक्रवार, 21 अगस्त , 2026

वर्ष : 11 । अंक: 352

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर कोई मोती गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

संक्षेप

दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से हटाए सुरक्षा घेरा-बैरिकेड, इस्लामाबाद की इस हरकत के बाद लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और अहम कार्रवाई की है। भारतीय अधिकारियों ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लगाए गए बाहरी सुरक्षा घेरे को हटा दिया है। डिप्लोमैटिक परिसर की सुरक्षा के लिए सड़क पर लगाए गए ट्रैफिक बैरिकेड्स और कंक्रीट बोलाइर्स को भी हटाकर रास्ता खाली कर दिया गया है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि परिसर के चारों ओर बाड़ की तरह बनाया गया बाहरी सुरक्षा घेरा हटा दिया गया है। अधिकारियों ने ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड्स भी हटा दिए हैं। पहले सुरक्षा व्यवस्था के तहत इस इलाके में घेरा बनाकर आवागमन को नियंत्रित किया जाता था। भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानी मिशन के आसपास आवागमन को प्रतिबंधित करने वाली बाहरी सुरक्षा व्यवस्थाओं के कुछ हिस्सों को भी हटा दिया है। भारत का यह कदम पाकिस्तान की ओर से इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड्स और पार्किंग पोल हटाए जाने के करीब तीन दिन बाद आया है। इसके बाद नई दिल्ली में भी पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा घेरे को हटाया गया। भारतीय अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बनाए गए कुछ ढांचे और लाइन-मैनेजमेंट के लिए लगाए गए बैरियर हटा दिए गए हैं। ये बैरियर पाकिस्तानी मिशन के वीजा सेक्शन के पास लगाए गए थे। अधिकारियों के मुताबिक, ये ढांचे हाई कमीशन की मंजूर सीमा से बाहर एक गली में बनाए गए थे। इसी वजह से कार्रवाई करते हुए इन्हें हटा दिया गया।

'वंदे मातरम' पर कांग्रेस के रुख को देवेंद्र फडणवीस ने बताया 'मानसिक गुलामी', राहुल गांधी के पुणे दौरे पर भी कसा तंज

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के केवल दो अंतरे गाने के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोला है। फडणवीस ने कांग्रेस के इस कदम को भारतीय संविधान का अपमान और पार्टी की 'मानसिक गुलामी' का परिचायक करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगामी पुणे दौरे और उनके कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' पर भी तीखा तंज कसा है।फडणवीस ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से यह भी कहा कि उन्हेंजानकारी मिली है कि 22 अगस्त को पुणे में होने वाला राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम सिर्फ़ कांग्रेस नेताओं द्वारा चलाए जा रहे कॉलेजों के विद्यार्थियों तक ही सीमित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम खुली बातचीत के बजाय एकतरफा भाषण (मोनोलॉग) जैसा होगा। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने बुधवार को अपने 1937 के प्रस्ताव को मानने का फ़ैसला किया। इसके तहत अब पार्टी के सभी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' के सिर्फ दो ही अंतरे गाये जायेंगे। कांग्रेस का यह फैसला तब आया जब भाजपा ने उसके नेताओं पर पार्टी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण न गाकर उसका अपमान करने का आरोप लगाया।

'कांग्रेस ने 1937 में तुष्टिकरण के लिए देश के विभाजन की नींव डाली'

अमित शाह ने वंदे मातरम विवाद पर विपक्ष को घेरा

नई दिल्ली, एजेंसी। गृहमंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम से जुड़े विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही 1937 में तुष्टिकरण के लिए वंदे मातरम के दो हिस्से किए थे और देश के विभाजन की नींव डाली थी। देश एक बार वंदे मातरम को दो टुकड़ों में बंटने का असर देख चुका है और दोबारा ऐसा नहीं होने देगा। हालांकि, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में पूरा वंदे मातरम बजाया गया था। इस दौरान सोनिया गांधी किसी बात से नाखुश दिखी थीं। बाद में कांग्रेस नेताओं ने सफाई देते हुए कहा कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगा रही थीं, क्योंकि वह बहुत देर से खड़े थे। इस घटना के चार दिन बाद ही कांग्रेस ने कहा कि उनके नेता वंदे मातरम के दो ही छंद गाएंगे।

अमित शाह ने कहा, 'कल कांग्रेस पार्टी की कार्य सममिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 1937 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपिसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ।

पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही कांग्रेस

आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रेजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करें। अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। यह आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है। उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधाई सदनों में भी पुरजोर विरोध करेंगे।

कांग्रेस ने शहीदों का अपमान किया-शाह

गृहमंत्री ने कहा, 'आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150 वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की यह अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शनंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का निर्णय किया है। इस निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है। उन लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। जिन्होंने कई साल जेल में काटे।'

'पहले सीमाओं की अनदेखी हुई, अब शीर्ष प्राथमिकता'

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि देश की सीमा से सटे इलाके, जिनकी पहले अनदेखी की गई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शीर्ष प्राथमिकता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीमाई इलाकों में विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

किरेन रिजिजू ने एक्स पर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों माजा, गालेमो और तक्सिंग के दौरे का एक वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो में बुनियादी ढांचे के काम के लिए मशीनें चलती दिखीं। केंद्रीय मंत्री ने सेना के जवानों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। वीडियो में दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ हिमालयी इलाका भी दिखा जो सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है। एक्स पर पोस्ट करते हुए किरेन रिजिजू ने लिखा, 'कुछ लोग सीमा को लेकर लापरवाही से टिप्पणी कर देते हैं। सीमाई क्षेत्र मुश्किल हैं, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार सीमा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैं अरुणाचल प्रदेश के माजा, गालेमो, तक्सिंग इलाकों में गया ताकि बुनियादी ढांचे के काम तेज किए जा सकें। पहले सीमाओं की अनदेखी हुई थी लेकिन अब यह शीर्ष प्राथमिकता है।'

केंद्रीय मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब विपक्षी नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार चीनी घुसपैठ की जानकारी छिपा रही है। सीमा पर भारतीय क्षेत्र की ठीक से रक्षा नहीं कर रही है।इससे पहले बुधवार को आईएएनएस से विशेष बातचीत में किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस दावे को खारिज किया।

दक्षिण 24 परगना में पटाखा फैक्टरी में धमाका, पांच लोगों के घायल होने की खबर; पुलिस ने क्या कहा?

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में गुरुवार को पटाखा बनाने वाली फैक्टरी में धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में कम से कम पांच लोग घायल हुए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमाका दोपहर के समय चंपाहाटी इलाके की फैक्ट्री में हुआ। धमाके के बाद फैक्टरी में आग लग गई। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने फैक्टरी को आग की लपटों में घिरा देखा। वहां से घना धुआं निकल रहा था। अधिकारी ने कहा, धमाके में पांच लोग घायल हुए हैं। दमकल की एक टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि मामले की जांच चल रही है। इसका मकसद धमाके की सही वजह पता करना और यह जांचना है कि फैक्टरी के पास जरूरी लाइसेंस था या नहीं और वहां सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं।

भारत की विकास यात्रा में राजीव गांधी का भी अहम योगदान, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती की अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बड़ा बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में राजीव गांधी का भी अहम योगदान रहा है। राजनाथ सिंह के बयान के बाद सियासी पारा बढ़ सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत की विकास यात्रा में उनका भी अहम योगदान रहा है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की भूमिका भारत को आधुनिक, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने में अहम रही। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को विश्व में वर्तमान स्थान दिलाया और इसीलिए उन्हें भारत में

सूचना प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राजीव गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

वहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भारत के निर्माण और तरक्की के लिए आधुनिक तकनीक और नए विचारों को अपनाने में विश्वास जताया। इसके लिए यह बेहद जरूरी था कि युवाओं की भागीदारी और उनकी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समुचित व्यवस्था और अवसर प्रदान किए जाए।

पायलट ने लिखा, अपनी दूरदर्शिता से उन्होंने देश में आधुनिकरण की नई परिभाषा गढ़ी। कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण फैसलों ने देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। आज उनकी जयंती पर उन्हें हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं।

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, राजीव गांधी न केवल भारत के प्रधानमंत्री थे बल्कि युवाओं के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे, एक ऐसे नेता जिनका मानना था कि युवा भारतीय न केवल भविष्य हैं बल्कि वे शक्ति हैं जो एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत और आर्थिक रूप से सशक्त भारत का उनका विजन कांग्रेस पार्टी के लिए प्रेरणा और जिम्मेदारी है। राजीव जी को उनकी 82वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर पुलिस का कड़ा प्रहार, सादे कपड़ों में छापा मारकर 224 गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति

अलीगढ़। अलीगढ़ जिले में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के आरोप में 224 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नीरज कुमार ने बृहस्पतिवार को इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और शराब की दुकानों के आसपास खुलेआम शराब पीकर आम नागरिकों और राहगीरों के साथ अभद्रता करते हैं।

सादे कपड़ों में तैनात रही पुलिस टीम

इन शिकायतों का कड़ा संज्ञान लेते हुए बुधवार रात सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की विशेष टीमें बनाकर संदिग्ध इलाकों में अचानक छापेमारी की गई। इस दौरान कई स्थानों पर लोग खुलेआम शराब पीते पाए गए। इसके अलावा, कई शराब की दुकानों पर नियमों की अनदेखी करते हुए ग्राहकों को मौके पर ही शराब परोसते हुए पाया गया, जो कि कानूनन अपराध है।

1,000 से अधिक लोगों का हुआ एल्कोहल टेस्ट

आधी रात तक चले इस सघन अभियान के दौरान पुलिस ने 1,000 से अधिक लोगों का ब्रेथ एनालाइजर के जरिए एल्कोहल टेस्ट किया। इनमें से नियमों का उल्लंघन करने और नशे में पाए जाने पर 224 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शांति भंग और नियमों के उल्लंघन के आरोप में पकड़े गए सभी आरोपियों को बाद में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है। एसएसपी नीरज कुमार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के औचक निरीक्षण और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

ई20 के बाद अब जहाजों के ईंधन पर बड़ा बदलाव, 2029 से 10प्रतिशत बायोफ्यूल अनिवार्य करने की तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने भारतीय तटीय जलक्षेत्र में कम कार्बन और रिन्यूएबल फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक ड्राफ्ट रोडमैप जारी किया है। इसका उद्देश्य इंडियन कोस्टल ट्रेड में चलने वाले जहाजों को धीरे-धीरे क्लीनर फ्यूल की ओर ले जाना और समुद्री परिवहन से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मरीन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी दस्तावेज के मुताबिक, बायोफ्यूल और उसके ब्लेंड का इस्तेमाल समुद्री परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करने का अपेक्षाकृत आसान और किफायती तरीका हो सकता है। खास बात यह है कि ड्रॉप-इन बायोफ्यूल के इस्तेमाल के लिए मौजूदा जहाजों के फ्यूल सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं पड़ सकती।

दादा भूसे का इस्तीफा मांगा

अभिजीत दीपके ने लातूर में सरकारी स्कूलों की बदहाली पर सवाल उठाए

नई दिल्ली, एजेंसी। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) के संयोजक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे के इस्तीफे की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि सरकारी विद्यालयों की हालत दयनीय है और छात्रों की तुलना में ''मंत्रियों के कुत्तों को भी बेहतर सुविधाएं'' मिलती हैं। कॉजपा ने पिछले सप्ताह 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू किया था। दीपके ने लातूर की औसा तहसील के उजनी गांव स्थित एक जिला परिषद स्कूल का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि विद्यालयों की स्थिति के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और मंत्रियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कई विद्यालयों में अब भी अच्छी कक्षाओं, बेंच, शौचालय और उन तक पहुंचने के सुरक्षित मार्ग जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विद्यालयों में छात्रों के लिए ''जानवरों से भी बदतर'' हालात हैं। दीपके ने कहा, ''यह छात्रों की जिंदगी का सवाल है। जब नेता छात्रों के लिए कुछ नहीं कर रहे तो लोग उन्हें वोट क्यों दें? क्या लोग उन्हें केवल हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए वोट देते हैं? लोगों को देखना चाहिए कि उनके बच्चे किन हालात में पढ़ रहे हैं।

राहुल ने राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि, लिखा–आपकी सीख मेरी शक्ति है और आपकी यादें मेरी हिम्मत

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीयों के बीच सद्भावना, हर दिल में करुणा और हर नागरिक को न्याय और लोकतंत्र में समान अधिकार। पापा, आपकी ये सीख मेरी शक्ति है और आपकी यादें मेरी हिम्मत। आपके सपनों का भारत बनाने का संकल्प हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा। वहीं, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भारत रत्न राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर गहरे स्नेह और सम्मान के साथ याद कर रहे हैं। वे एक दूरदर्शी और गतिशील नेता थे, जिन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया और हमारे देश को

21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए उसमें बदलाव लाए। केसी वेणुगोपाल ने लिखा, आज, लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। उनका मकसद देश के लिए राजीव जी के विजन को पूरा करना और उसी ऊर्जा व उत्साह के साथ पार्टी को आगे बढ़ाना है, जो वे लेकर आए थे। उनका जीवन-सफर बहुत जल्द समाप्त हो गया और भारत की एकता के लिए दी गई उनकी सर्वोच्च कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। राजीव जी, हम आपको बहुत याद करते हैं! इस अवसर पर वीर भूमि पर राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज जब हम राजीव गांधी की 82वीं जयंती मना रहे हैं और देशभर में युवाओं के बीच बढ़ती बेचैनी और हलचल को देख रहे हैं, तब यह याद करना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही थे जिन्होंने संविधान में संशोधन कर मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की और 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया।

जयराम रमेश ने लिखा,जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। 1988 की नई शिक्षा नीति लेकर आए, जिसने कई अन्य नए प्रयासों के साथ देशभर में नवोदय विद्यालयों का नेटवर्क स्थापित किया। देश के सभी जिलों को कवर करने वाले नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्थापना की (जिसका नाम अब बदलकर माई भारत कर दिया गया है) और भारत को निर्णायक रूप से आईटी युग में लेकर गए, जिससे रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा हुए।

वैवाहिक विवाद में बच्चे का हो सकता है डीएनए टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक अहम फैसले में कहा है कि कुछ परिस्थितियों में शादी के दौरान जन्मे बच्चे के पितृत्व की जांच के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। अदालत ने यह फैसला उस मामले में सुनाया, जिसमें पति ने पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी और दावा किया था कि वह बच्चे का जैविक पिता नहीं है। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने महिला की याचिका खारिज कर दी। महिला ने बच्चे के पितृत्व परीक्षण का विरोध करते हुए कहा था कि किसी व्यक्ति को जबरन डीएनए टेस्ट कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उसने मांग की थी कि पति की तलाक याचिका पर बिना डीएनए टेस्ट के फैसला किया जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि अगर महिला अपने पति के प्रति वफादार है, तो फिर डीएनए टेस्ट का विरोध करने की जरूरत क्यों है।

तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, रेप केस में 10 साल की सजा मिली थी

नई दिल्ली, एजेंसी। तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने 2013 के रेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने 2021 में उन्हें बरी करने के फैसले को पलट दिया था और कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने मामले के अहम सबूतों का सही ढंग से आकलन नहीं किया था। गोवा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और तेजपाल की सज़ा को 10 साल से बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की है। सरकार का तर्क है कि यह सज़ा अपराध की गंभीरता के हिसाब से पर्याप्त नहीं है।

'7 लाख दो, सरकारी नौकरी पाओ...', फर्जी आईएएस विप्रा शर्मा गैंग का पर्दाफाश, यूनिवर्सिटी क्लर्क भी था ठगी में शामिल

>> बरेली में सरकारी नौकरी के नाम ठगी करने के नाम पर नया खुलास >> रुहेलखंड विश्वविद्यालय का क्लर्क करता था फर्जी आईएस बहनों की मदद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली में खुद को आईएएस अधिकारी बताकर बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ो रुपये की ठगी करने वाले गैंग की परतें अब लगातार खुल रही हैं। गैंग की मुख्य आरोपी विप्रा शर्मा और उसकी बहन के बारे में पुलिस पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। आरोप है कि दोनों बहनें खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों को सरकारी नौकरी का भरोसा देती थीं। लोगों पर रौब जमाने के लिए लग्जरी कार पर नीली बत्ती लगाकर चलने और खुद को बड़ा अधिकारी बताने का भी आरोप सामने आया था।

पुलिस दोनों बहनों को कई महीने पहले जेल भेज चुकी है और गैंग से जुड़ी संपत्तियों को भी चिह्नित किया जा चुका है। अब इस मामले में नया खुलासा रुहेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़ा है। विश्वविद्यालय में क्लर्क के पद पर तैनात देवप्रकाश का नाम भी ठगी के एक मामले में सामने आया है। बारादरी थाने में उसके खिलाफ दोबारा रिपोर्ट दर्ज हुई है। आरोप है कि देवप्रकाश छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को विप्रा तक पहुंचाने और नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाने में मदद करता था।

शाहजहांपुर निवासी पुष्पेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध पुवायां के एक महाविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के दौरान उनकी पहचान विश्वविद्यालय के क्लर्क देवप्रकाश से हुई। आरोप है कि देवप्रकाश ने बताया कि उसका विप्रा शर्मा से संपर्क है और वह सरकारी नौकरी लगवा सकती हैं। नौकरी न लगने पर रकम वापस कराने का भरोसा भी दिया गया।

इसके बाद देवप्रकाश के साथ पुष्पेंद्र गोल्डन ग्रीन पार्क स्थित विप्रा के घर पहुंचे। आरोप है कि यहां राजस्व विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे सात लाख रुपये ले लिए गए। काफी समय बाद भी नौकरी नहीं लगी तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। जांच के दौरान पता चला कि विप्रा के नाम से पहले भी सरकारी नौकरी के नाम पर कई लोगों से रकम लेने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं।

फर्जी नियुक्ति पत्र देकर भेज देते थे नौकरी करने

संजय नगर निवासी अरविंद कुमार ने भी विप्रा के खिलाफ बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अरविंद के मुताबिक उनकी विप्रा से पहचान एक कपड़े की दुकान पर हुई थी। आरोप है कि विप्रा ने फोन कर उन्हें गोल्डन ग्रीन पार्क स्थित घर बुलाया और सरकारी नौकरी लगवाने का भरोसा देकर चार लाख रुपये लिए। इसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। अरविंद जब नियुक्ति पत्र लेकर शाहजहांपुर पहुंचे तो वहां पहुंचने पर फर्जीवाड़े का पता चला। इसी तरह पुलिस के सामने आए मामलों में आरोप है कि गैंग पहले बेरोजगार युवाओं को अपने प्रभाव में लेता था। खुद को आईएएस अधिकारी बताकर सरकारी विभाग में नौकरी लगवाने का भरोसा दिया जाता था। नौकरी के पद के हिसाब से लाखों रुपये मांगे जाते थे। रकम मिलने के बाद फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पीड़ित को संबंधित विभाग में भेज दिया जाता था।

पुलिस ने संपत्तियां चिह्नित कीं, अब नए नाम सामने आ रहे

विप्रा शर्मा के खिलाफ अलग-अलग थानों में लगातार मुकदमे दर्ज होते रहे हैं। पुलिस कार्रवाई के दौरान उसके साथ जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई। गैंग से जुड़ी संपत्तियों को चिह्नित करने की कार्रवाई भी की गई है। पुलिस का कहना है कि ठगी से अर्जित संपत्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक, इस पूरे मामले में अब तक 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। अलग-अलग मामलों में विप्रा, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम सामने आए हैं। कई आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस की जांच अभी जारी है और नए पीड़ितों की शिकायतें सामने आने के साथ गैंग से जुड़े नए लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अब रुहेलखंड विश्वविद्यालय के क्लर्क देवप्रकाश का नाम सामने आने से मामला और गंभीर हो गया है। आरोप है कि उसके खिलाफ पहले भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उसे कृषि संकाय में भेजे जाने की बात सामने आई है। वहीं एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि विप्रा गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। नए मामलों में सामने आ रहे आरोपियों की भूमिका की जांच हो रही है। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। ठगी से अर्जित संपत्तियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

वीडियो बनाने पर भड़के बीडीओ

आर्यावर्त संवाददाता

सुल्तानपुर। विकास खंड अखंडनगर की ग्राम पंचायत गिधौना में विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं की जांच करने पहुंचे खंड विकास अधिकारी का रवैया ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि जांच के दौरान जब उन्होंने पारदर्शिता के लिए मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो बीडीओ नाराज हो गए और कथित तौर पर साफ शब्दों में कह दिया कि वीडियो बनाओगे तो मैं जांच नहीं करूंगा। ग्रामीणों के वीडियो बनाना जारी रखने पर अधिकारी कथित रूप से बिना स्थलीय सत्यापन किए ही वापस लौट गए। मामला तब गरमाया जब ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर से की। सीडीओ के निर्देश पर बीडीओ को मौके पर पहुंचकर जांच करनी थी। इसी क्रम में बीडीओ टीम के साथ गिधौना पहुंचे। ग्रामीणों के मुताबिक जांच शुरू होने से पहले ही मौके पर मौजूद लोगों ने कार्रवाई की पारदर्शिता के लिए मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का दावा है कि वीडियो बनाए जाने पर बीडीओ ने आपत्ति जताई और वीडियो बंद करने को कहा। जब ग्रामीणों ने वीडियो बनाना बंद नहीं किया तो अधिकारी ने जांच नहीं करने की बात कही और मौके से लौट गए। ग्रामीणों का आरोप है कि इस दौरान न तो विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन हुआ और न ही कथित अनियमितताओं की मौके पर जांच की गई।

डायरिया के प्रति जागरूकता की अलख जगाएगा केमिस्ट एसोसिएशन

आर्यावर्त संवाददाता

उन्नाव। केमिस्ट एसोसिएशन ने डायरिया से शून्य से पांच साल तक के बच्चों को सुरक्षित बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का संकल्प लिया है। इसके लिए एसोसिएशन खासकर डायरिया के प्रति जागरूकता पर जोर देगा और मेडिकल स्टोर पर आने वालों को डायरिया के बारे में जानकारी देने के साथ ही उससे बचाव व रोकथाम के उपायों के बारे में भी बताएगा और उचित उपचार के लिए चिकित्सक के पास जाने की सलाह भी देगा। यह फैसला बृहस्पतिवार को स्थानीय एक होटल में केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मयंक बाजपेयी की उपस्थिति में हुई केमिस्ट एसोसिएशन की अभिमुखीकरण कार्यशाला में लिया गया। पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू (KENVUE) के सहयोग से जनपद में चल रहे 'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता ड्रग इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने की।

कार्यशाला में पीएसआई इंडिया के गजेंद्र सिंह ने 'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम के बारे में बताया कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 13 और बिहार के तीन जनपदों में चलाया जा रहा है, जिसमें शून्य से पांच साल तक के बच्चों की डायरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को शून्य करना और दस्त प्रबंधन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि डायरिया नियंत्रण और रोकथाम में केमिस्ट बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस पर केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मयंक बाजपेई ने कार्यक्रम को सफल बनाने में हरसम्भव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि समुदाय में डायरिया को लेकर आज भी भ्रांतियां व्याप्त हैं, जिनको दूर करना बहुत जरूरी है। इसमें वह भरपूर सहयोग करेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर उन्नाव अशोक कुमार ने केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों की डायरिया पर पीएसआई इंडिया द्वारा कराई जा रही कार्यशाला की सराहना की एवं आश्वासन दिया कि आगे भी वह ऐसे आयोजनों में सहयोग करेंगे I उन्होंने कहा कि डायरिया से अपने साथ ही बच्चों को सुरक्षित बनाने के लिए घर पर ओआरएस और जिंक अवश्य रखें क्योंकि यही इसका सही उपचार है I जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र जाकर चिकित्सक की सलाह अवश्य लें I कार्यशाला में केमिस्ट लिफाफा एवं पोस्टर का वितरण मौजूद दवा व्यापारियों को किया गयाI

कार्यशाला के अन्त में केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मयंक बाजपेई ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला में केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ ही पीएसआई इंडिया से अशरफ हुसैन आदि उपस्थित रहे।

चौक घंटाघर के कायाकल्प की तैयारी तेज, 34 लाख रुपये होंगे खर्च

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। शहर की ऐतिहासिक पहचान चौक घंटाघर अब जल्द ही नए और आकर्षक रूप में नजर आएगा। नगर पालिका परिषद ने घंटाघर के मरम्मत, जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की योजना तैयार की है। गुरुवार को पालिकाध्यक्ष प्रवीन कुमार अग्रवाल की मौजूदगी में लखनऊ से पहुंची इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और इलेक्ट्रिशियनों की टीम ने घंटाघर का निरीक्षण कर कार्ययोजना को अंतिम रूप देने की दिशा में जरूरी जानकारी जुटाई। पालिकाध्यक्ष ने बताया कि चौक घंटाघर का पिछली बार वर्ष 2007-08 में सौंदर्यीकरण कराया गया था। समय बीतने के साथ भवन की मरम्मत और पुरानी घड़ियों को बदलने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी को देखते हुए अब घंटाघर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ आकर्षक प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। योजना के तहत घंटाघर के चारों ओर लगी पुरानी घड़ियों को हटाकर नई डिजिटल घड़ियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा आधुनिक फल्ड लाइटिंग से इमारत को रोशन किया जाएगा। भवन की आवश्यक मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य भी कराया जाएगा। नगर पालिका के अनुसार पूरे कार्य पर करीब 34 लाख रुपये खर्च होने का प्रस्ताव है। आगामी दुर्गा पूजा सहित अन्य त्योहारों को देखते हुए 20 सितंबर तक सौंदर्यीकरण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्य पूरा होने के बाद त्योहारों के दौरान आकर्षक रोशनी से जगमगाता घंटाघर शहरवासियों और राहगीरों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगा। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी लाल चन्द्र सरोज, सहायक अभियंता सिविल संतोष कुमार, अवर अभियंता सिविल नीलम कुमारी, मार्ग प्रकाश विभाग के अजय तिवारी, सुनील श्रीवास्तव, हनुमान सिंह समेत लखनऊ से आई तकनीकी टीम और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

विकास की रोशनी में कमीशनखोरी का अंधेरा

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। बल्दीराय तहसील क्षेत्र में विकास के नाम पर लगाई गई स्ट्रीटलाइटें अब खुद सरकारी व्यवस्था में व्याप्त बड़े भ्रष्टाचार की बदहाली की कहानी बयां कर रही हैं। लाखों रुपये खर्च कर सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में लगाई गई रोशनियां लंबे समय से बंद पड़ी हैं, लेकिन उनकी मरम्मत कराने की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। सवाल यह है कि जब लाइटें लगाने के समय बजट और व्यवस्था सक्रिय रहती है तो खराब होने के बाद उनकी सुध लेने में जिम्मेदारों को इतनी देर क्यों लगती है? हरौरा बाजार नहर चौराहा स्थित पुलिस चौकी की स्ट्रीटलाइट करीब छह माह से बंद बताई जा रही है। चौराहा अंधेरे में डूब जाता है। पीरोसरैया ठाकुरबाबा चौराहे की लाइट लगभग चार माह से खराब है। बल्दीराय कस्बे और बहुरावां बाजार में आशाराम यादव के दरवाजे के पास लगी स्ट्रीटलाइट करीब दो वर्ष से बंद पड़ी है। ऐंजर में रूपेश द्विवेदी, रामउचित द्विवेदी के दरवाजे की स्ट्रीटलाइट लगभग एक वर्ष से खराब है, जबकि डीह मोड़ भवानीगढ़ की लाइट भी करीब एक साल से अंधेरा फैला रही है। ठीक यही हाल तिरहुति बाजार के स्ट्रीटलाइट की है 18 मजह से बंद है।

इन बंद स्ट्रीटलाइटों की लंबी सूची, व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यदि सार्वजनिक धन से लाइटें लगाई गई हैं तो उनके रखरखाव की जिम्मेदारी किस विभाग, संस्था या एजेंसी की है ? क्या लाइट लगाने के बाद उसकी गुणवत्ता और वारंटी की जांच हुई ? खराब लाइटों की मरम्मत के लिए कोई शिकायत रजिस्टर या नियमित निरीक्षण व्यवस्था है ? यदि है तो कहां हैं जिम्मेदार अथवा क्षेत्र के जन प्रतिनिधि । क्या प्रशासन को ऐसे जन समस्याओं के प्रति संज्ञेय नही होना चाहिए ? जिम्मेदारों की भूमिका पर ये बड़े सवाल हैं ?

स्थानीय लोगों का आरोप है कि विकास कार्यों में कमीशनखोरी के कारण गुणवत्ता से समझौता किया जाता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच जरूरी है। प्रशासन को चाहिए कि स्ट्रीटलाइटों की खरीद, स्थापना, भुगतान, गुणवत्ता, वारंटी और मरम्मत संबंधी अभिलेखों की जांच कराए। यदि कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग या अनियमितता, भ्रष्टाचार सामने आती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। अंधेरे में डूबे चौराहे और बाजार केवल खराब लाइटों की समस्या नहीं, बल्कि जवाबदेही के अंधेरे के भी प्रतीक हैं। अब देखना है कि प्रशासन इन बंद पड़ी स्ट्रीटलाइटों को रोशनी देता है या इस बड़े भ्रष्टाचार पर पर्दा डालते हुए फाइलों में ही विकास चमकाता रहेगा।

विपिन प्रकाश ने शोक संतप्त परिवारों से मिलकर जताई संवेदना

आर्यावर्त संवाददाता

जयसिंहपुर/सुलतानपुर। सपा नेता विपिन प्रकाश सिंह 'दीपक' ने जयसिंहपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंचकर दिवंगत लोगों के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिजनों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने शुकुल दुलैचा, खटवर, महादेवपुर, मैरी रंजीत, अठैसी कुर्मी विजौली, अकारीपुर, मैरी संग्राम, कैथवारा, जयसिंहपुर, ढेमा-उदयपुर भदिलापुर, हटुई, पीढ़ी और दरपीपुर सहित विभिन्न गांवों में पहुंचकर शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान सड़क हादसे, डूबने, करंट लगने और हार्ट अटैक से हुई मौतों पर उन्होंने गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी। इसके अलावा सेमरी के सोनूपारा में आयोजित भंडारे में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। अठैसी स्थित हनुमान मंदिर के भंडारे में भी सहभागिता कर मुख्य पुजारी संजय सिंह से आशीर्वाद लिया।

तेज रफ्तार बस ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, सात बच्चे घायल, ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। जिले में मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के सुजानगंज मार्ग पर उकनी गांव के पास गुरुवार सुबह तेज रफ्तार निजी बस की टक्कर से डीआरएम पब्लिक स्कूल मधुपुर की स्कूल वैन पलट गई। हादसे के समय वैन में करीब नौ बच्चे सवार थे। वैन पलटते ही बच्चों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में सात बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य बच्चों को भी चोटें आईं।

स्कूल वैन मुंगराबादशाहपुर की ओर से सुजानगंज जा रही थी इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही बस के चालक ने ओवरटेक करने का प्रयास करते हुए वैन में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही स्कूल वैन सड़क किनारे पलट गई। आसपास के लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बच्चों को वैन से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची मुंगराबादशाहपुर थाना पुलिस ने भी राहत कार्य में सहयोग किया।

हादसे में आदित्य यादव (11) पुत्र प्रमोद यादव निवासी जखनियां, थाना पवारा को भर्ती कराया गया। वहीं सिद्धार्थ यादव (10) पुत्र राजेश यादव निवासी जखनियां, थाना पवारा, प्रभाष यादव (12) पुत्र प्रदीप यादव निवासी माडवादोडक, थाना पवारा, अनिरुद्ध यादव (10) पुत्र अजय यादव निवासी माडवादोडक, थाना पवारा और आर्यन यादव (10) पुत्र प्रमोद यादव निवासी जखनियां, थाना पवारा आकाश तिवारी (10) पुत्र हृदय तिवारी निवासी जखनियां पवांरा, शिवम तिवारी (8) पुत्र राकेश तिवारी जखनिया पवांरा गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल सीएचसी सुजानगंज भेजा गया।

तीन बच्चे रेफर

प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए सिद्धार्थ यादव, प्रभाष यादव और आदित्य यादव को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अन्य घायल बच्चों का उपचार सीएचसी में किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष निरीक्षक गजानन चौबे, चौकी प्रभारी धनंजय राय और क्षेत्राधिकारी प्रतिमा वर्मा मौके पर पहुंचीं और घटना की जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्रवाई में जुट गए।

हादसे की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक भी मौके पर पहुंच गए तथा अपने-अपने बच्चों का हाल जाना। थानाध्यक्ष गजानंद चौबे ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे में शामिल बस को हिरासत में ले लिया गया है।

घायल बच्चों का हाल जानने के लिए डीएम सैमुअल पॉल एन दोपहर में जिला अस्पताल पहुंचे। डीएम ने मौके पर डॉक्टरों की टीम से बातचीत कर उचित इलाज के लिए कहा।वहीं मामले की छानबीन के निर्देश दिए।

रेलकर्मियों के लिए खुशखबरी : छोटी–मोटी गलतियों से नहीं छिनेगा 'दुर्घटनामुक्त सेवा पुरस्कार', बोर्ड का बड़ा फैसला

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब गैर-सुरक्षा संबंधी मामलों में मिलने वाले मामूली दंड (माइनर पेनाल्टी) रेलवे कर्मचारियों के 'दुर्घटनामुक्त सेवा पुरस्कार' (Accident Free Service Award) की राह में रोड़ा नहीं बनेंगे। रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों की पात्रता को लेकर जारी भ्रम को खत्म करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण और नीतिगत फैसला लिया है।

नए आदेश के तहत अब कार्यस्थल की सफाई, सामान्य व्यावसायिक कर्तव्यों या सुरक्षा से इतर अन्य गैर-सुरक्षात्मक मामलों में हुई मामूली चूकों के लिए दिए गए माइनर पेनाल्टी को पुरस्कार की पात्रता तय करते समय नहीं गिना जाएगा। पूर्व में सुरक्षा से असंबंधित छोटी-मोटी चूकों पर भी कर्मचारियों के पुरस्कार रोक दिए जाते थे या उनकी राशि में कटौती कर ली जाती थी। कर्मचारियों द्वारा लगातार उठाए जा रहे इस मुद्दे के बाद रेलवे बोर्ड ने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।

व्याख्या के अंतर को खत्म करने की कवायद

रेलवे बोर्ड ने सभी भारतीय रेल के महाप्रबंधकों (GMs) को पत्र जारी कर निर्देशित किया है। बोर्ड ने माना कि अलग-अलग जोनों में नियमों की भिन्न व्याख्या के कारण एकरूपता प्रभावित हो रही थी। समीक्षा के बाद बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल वही कर्मचारी दुर्घटनामुक्त सेवा पुरस्कार के लिए अयोग्य माने जाएंगे, जिन्हें किसी गंभीर कदाचार के लिए बड़ा दंड (मेजर पेनाल्टी) मिला हो। इस फैसले से निष्ठा से सेवा दे रहे हजारों रेलकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा।

महिला सशक्तिकरण अभियान में छात्राओं को किया जागरूक

बल्दीराय/सुलतानपुर। महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता अभियान के तहत बल्दीराय थाना पुलिस ने कैप्टन बालचंद इंटर कॉलेज, मीरपुर में छात्राओं व महिलाओं को सुरक्षा, अधिकार, आत्मनिर्भरता और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। पुलिस ने घरेलू हिंसा, बाल विवाह, छेड़छाड़, लैंगिक अपराध और सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल के प्रति जागरूक करते हुए किसी भी समस्या पर तत्काल पुलिस की मदद लेने की अपील की। कार्यक्रम में उपनिरीक्षक राजदेव यादव, कांस्टेबल विजय कुमार तथा महिला कांस्टेबल सविता व रिंकी मौजूद रहीं। प्रधानाचार्य पवन कुमार यादव, अध्यापिकाओं और छात्राओं ने अभियान की सराहना की।

डेयरी क्षेत्र में 6937 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 11 हजार नए रोजगार की उम्मीद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उन्नत नस्ल के गोवंश को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में डेयरी क्षेत्र की भूमिका मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में दुग्ध विकास विभाग की ओर से 'नंद बाबा दुग्ध मिशन' और दुग्ध प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रचार-प्रसार तथा डेयरी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित मंडलवार 'डेयरी कॉन्क्लेव-स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद' श्रृंखला के तहत बरेली में कार्यशाला आयोजित की गई।भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली में आयोजित कार्यक्रम में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बरेली, मुरादाबाद और लखनऊ मंडल कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की समृद्ध संभावनाओं वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ये मंडल प्रदेश के डेयरी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभा सकते हैं।उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल दूध उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि दूध प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, कोल्ड चेन और डेयरी उद्योग की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों और पशुपालकों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और निवेश की सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।अपर मुख्य सचिव पशुधन एवं दुग्ध विकास मुकेश कुमार मेश्राम ने देशी नस्ल के गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के बहुआयामी लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभाव सीधे पशुपालकों और गोपालकों के जीवन स्तर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने उन्नत देशी गोवंश, समृद्ध निवेश, सुरक्षित भविष्य और खुशहाल उत्तर प्रदेश के संकल्प को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया।दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के. ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। किसानों को सुनिश्चित बाजार, पारदर्शी मूल्य निर्धारण और स्थायी आय उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन और दुग्ध नीति-2022 के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादन, आधुनिक डेयरी विकास और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।उन्होंने बताया कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत बरेली, मुरादाबाद और लखनऊ मंडल में करीब 2200 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1200 लाख रुपये से अधिक की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। वहीं दुग्ध नीति-2022 के तहत इन मंडलों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1100 लाख रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है।कार्यक्रम में प्रस्तुत निवेश संबंधी आंकड़ों के अनुसार, बरेली मंडल में 2712 करोड़ रुपये, मुरादाबाद मंडल में 2085 करोड़ रुपये और लखनऊ मंडल में 2150 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार तीनों मंडलों में कुल करीब 6937 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। इन प्रस्तावों से लगभग 11 हजार नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है।बरेली मंडल के अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है और डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला बन चुका है। बरेली मंडल दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, दुग्ध प्रसंस्करण और डेयरी उद्यमिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अधिकारियों ने कहा कि किसानों, पशुपालकों, महिलाओं और युवाओं को डेयरी क्षेत्र से जोड़कर उनकी आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।कार्यक्रम में नंद बाबा दुग्ध मिशन के विभिन्न लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा कीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने बदल दी जिंदगी, संतकबीरनगर के जितेंद्र कुमार को मिला पक्का घर तो लौटा सम्मान और सुकून

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की मूलभूत जरूरतों में शामिल हैं। इन तीनों में एक सुरक्षित और पक्का मकान परिवार को न केवल सुरक्षा देता है, बल्कि सम्मान और बेहतर जीवन की नींव भी तैयार करता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अपना पक्का घर बनाना लंबे समय तक सपना बना रहता है। ऐसे ही जरूरतमंद परिवारों के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ने उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव किया है।प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपना घर बनाने में सक्षम नहीं थे। केंद्र और प्रदेश सरकार की इस पहल से आवासविहीन परिवारों को सुरक्षित आशियाना मिलने के साथ उनके जीवन में स्थायित्व, आत्मविश्वास और सम्मान भी आया है।इस योजना से लाभान्वित संतकबीरनगर जिले के नगर पंचायत हरिहरपुर के मोहल्ला जवाहर नगर, वार्ड संख्या छह निवासी जितेंद्र कुमार यादव पुत्र विश्राम यादव की कहानी इसका उदाहरण है। मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले जितेंद्र कुमार के लिए कभी पक्का मकान बनाना आसान नहीं था। उनका परिवार लंबे समय तक जर्जर कच्चे मकान में रहने को मजबूर था।जितेंद्र कुमार बताते हैं कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण घर का खर्च चलाना ही मुश्किल था। जिस मकान में उनका परिवार रहता था, उसकी हालत बेहद खराब थी। दीवारों में दरारें थीं और छत कभी भी गिरने का खतरा बना रहता था।

कालीचरण पीजी कालेज के युवा बने नशा मुक्त अभियान के राजदूत : डॉ. सूर्यकांत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। कालीचरण पीजी कॉलेज, लखनऊ में बृहस्पतिवार को ''नशा मुक्त फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान'' के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रबंधक इं. वी.के. मिश्र ने की। अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा कि ''विकसित भारत के सपने को सच करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा, और वही युवा शक्ति नेतृत्व और सृजन कर सकती है, जो नशे से मुक्त हो।'' कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता डॉ. सूर्यकान्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ़ रेस्पिरेटरी मेडिसिन किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ने युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि मेरा प्रयास है कि कालीचरण पीजी कॉलेज के युवा नशा मुक्त अभियान के राजदूत बनें। भारत के युवाओं का नशा मुक्त होना स्वस्थ भारत के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नशे से 40 तरह के कैंसर और 25 तरह की अन्य जानलेवा बीमारियां होती हैं । जब कोई व्यक्ति सिगरेट का नशा करता है तो 30 प्रतिशत वह अपने को और 70 प्रतिशत अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तम्बाकू पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए उन्होंने नौ बार प्रधानमंत्री को चिठ्ठी लिखी है। कार्यक्रम में युवाओं को नशा मुक्त होने की शपथ दिलाते हुए कहा कि आपका दायित्व है कि जो आपके-अपने नशा कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग और मेडिकल सहायता से नशा छुडाने का प्रयास करें।

कार्यक्रम में सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. चन्दमोहन उपाध्याय ने कहा कि भारत देश में 18 करोड़ युवा नशे का शिकार हैं, जो कि बहुत ही चिन्ता का विषय है। नशे के भँवर में फंसकर हम अपना और अपने परिवार का विनाश कर लेते हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन शारीरिक शिक्षा विभाग की प्रो. डॉ. कल्याणी द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापिका प्रो. मीना कुमारी, प्रो. अर्चना मिश्रा, प्रो. वीएन मिश्र, डॉ. डी.सी.डी.आर पाण्डेय, डॉ. मनीषा सिंह, डॉ. अल्का द्विवेदी सहित महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक गण एवं भारी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

पीड़ितों और बच्चों से संवेदनशील संवाद के लिए 68 रिक्रूट आरक्षियों को दिया गया प्रशिक्षण

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और समावेशी पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कमिश्नरेट लखनऊ में वर्ष 2025 बैच के रिक्रूट आरक्षियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। 20 अगस्त को रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित संगोष्ठी सदन में आयोजित कार्यशाला का विषय "पीड़ितों एवं बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व संवेदनशील संवाद कैसे स्थापित किया जाए" रहा।उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के क्रम में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमिश्नरेट लखनऊ के सभी थानों से वर्ष 2025 बैच के 68 रिक्रूट आरक्षियों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य नवआरक्षियों को संवेदनशील, सजग और प्रभावी प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले पुलिसकर्मी के रूप में तैयार करना रहा।प्रशिक्षण सत्र में यूनिसेफ की डिविजनल कंसल्टेंट रिजवाना परवीन ने प्रतिभागियों को पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने के व्यवहारिक तरीकों की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि घटनास्थल अथवा थाने पर पहुंचने के बाद पीड़ित की बात धैर्यपूर्वक सुनना, उसकी भावनात्मक स्थिति को समझना और उसे आवश्यक सहयोग एवं सुरक्षा का भरोसा दिलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।कार्यशाला में संवाद कौशल और व्यवहारिक विकास के साथ महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े विभिन्न कानूनों और प्रावधानों की जानकारी दी गई। इनमें घरेलू हिंसा से संबंधित कानून, किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम प्रमुख रहे। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका एवं कार्यप्रणाली के बारे में भी प्रतिभागियों को बताया गया।प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में आवश्यक सहयोग, संरक्षण तथा विधिक प्रक्रिया को लेकर भी पुलिसकर्मियों को व्यावहारिक जानकारी दी गई, ताकि वे पीड़ितों के साथ संवेदनशील व्यवहार करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें।कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार और पुलिस उपायुक्त मुख्यालय अमित कुमावत के मार्गदर्शन में किया गया। पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा ममता रानी चौधरी के निर्देशन तथा सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध शाहिदा नसरीन के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण सत्र संपन्न हुआ।

एग्रीगेटर पॉलिसी लागू, ऑनलाइन हुआ पोर्टल

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ऐप आधारित परिवहन और वितरण सेवाओं को व्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइन के तहत प्रदेश में लागू एग्रीगेटर पॉलिसी से संबंधित पोर्टल upmalfleet.com को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब एग्रीगेटर और वितरण सेवा प्रदाताओं को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत वर्तमान में कार्यरत सभी एग्रीगेटरों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तत्काल आवेदन करना होगा। वहीं कोई भी नया एग्रीगेटर बिना लाइसेंस प्राप्त किए एग्रीगेटर अथवा वितरण सेवा प्रदाता के रूप में अपना संचालन शुरू नहीं कर सकेगा। पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।उन्होंने बताया कि एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत आवेदन शुल्क 25 हजार रुपये और लाइसेंस जारी करने की फीस पांच लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा एग्रीगेटर के बेड़े में शामिल वाहनों की संख्या के आधार पर सुरक्षा राशि जमा करने का प्रावधान किया गया है। 100 बसों अथवा 1000 अन्य मोटर वाहनों तक के लिए 10 लाख रुपये, 1000 बसों अथवा 10 हजार अन्य मोटर वाहनों तक के लिए 25 लाख रुपये और 1000 से अधिक बसों अथवा 10 हजार से अधिक अन्य मोटर वाहनों के लिए 50 लाख रुपये की सुरक्षा राशि निर्धारित की गई है।

प्रदेश के संरक्षित स्मारकों के संरक्षण पर खर्च होंगे 15 करोड़ रुपये

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य पुरातत्व निदेशालय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान के तहत राज्य संरक्षित स्मारकों में व्यापक अनुरक्षण कार्य कराए जाने के लिए 15 करोड़ 5 लाख 31 हजार रुपये की धनराशि प्रस्तावित एवं अवमुक्त की गई है। इस धनराशि से होने वाले सिविल कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह धनराशि प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित महत्वपूर्ण संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, मरम्मत, सफाई और पुनरुद्धार पर खर्च की जाएगी। इसके तहत झांसी, लखनऊ, शामली, फिरोजाबाद और ललितपुर स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के स्मारकों में व्यापक अनुरक्षण कार्य कराए जाएंगे।उन्होंने बताया कि झांसी स्थित ठाकुरद्वारा की गढ़ी के सिविल कार्य के लिए करीब 498.96 लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है। इस धनराशि से स्मारक परिसर में वनस्पति उन्मूलन, दीवारों, छत और छज्जों पर लगे पत्थरों की रासायनिक सफाई कराई जाएगी। इसके साथ ही दीवारों पर बनी पेंटिंग की रासायनिक सफाई और संरक्षण कार्य तथा जर्जर दीवारों के प्लास्टर के रखरखाव का कार्य भी कराया जाएगा।पर्यटन मंत्री के अनुसार लखनऊ स्थित बड़ा शिवाला, सिद्धनाथ मंदिर सैठा में भी वनस्पति उन्मूलन और प्लास्टर के रखरखाव से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। वहीं शामली के प्राचीन गुंबद बंतीखेड़ा में भी संरक्षण कार्य कराया जाएगा, जिससे स्मारक की मूल संरचना को सुरक्षित रखा जा सके।फिरोजाबाद स्थित चंद्रवाड़ का किला भी संरक्षण योजना में शामिल है।

सरकारी खरीद में एमएसएमई के लिए बढ़े अवसर, जेम पर 20 लाख करोड़ की खरीद और 25 हजार नए वेंडर पंजीकृत

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सरकारी खरीद और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से जोड़ने के उद्देश्य से गोमती नगर स्थित पीएचडी हाउस में दो दिवसीय 'वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम-2026' का शुभारंभ हुआ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के एमएसएमई विकास कार्यालय, कानपुर और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में 200 से अधिक उद्यमियों, औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के सचिव प्रांजल यादव ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास में एमएसएमई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में 98 प्रतिशत से अधिक इकाइयां एमएसएमई श्रेणी की हैं और करीब 90 प्रतिशत इकाइयां सूक्ष्म उद्यम हैं। उन्होंने युवाओं को उद्यमिता की ओर आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार एमएसएमई की प्रमुख जरूरतों जैसे औद्योगिक भूखंड, वित्त, सब्सिडी और प्रोत्साहन को ध्यान में रखकर लगातार काम कर रही है।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का निर्यात करीब दो लाख करोड़ रुपये है। इसमें नोएडा का योगदान करीब 98 हजार करोड़ रुपये और गाजियाबाद का करीब 18 हजार करोड़ रुपये है। कानपुर, मुरादाबाद, भदोही, उन्नाव, बरेली, आगरा और वाराणसी जैसे औद्योगिक केंद्र भी प्रदेश के निर्यात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।प्रांजल यादव ने कहा कि वेंडर विकास और सरकारी खरीद एमएसएमई के लिए बड़े अवसर हैं। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर एमएसएमई की हिस्सेदारी करीब 45 प्रतिशत है और इसके तहत लगभग नौ लाख करोड़ रुपये की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से एमएसएमई ऑर्डर और चालान के आधार पर अपने बकाया भुगतान के बदले वित्त प्राप्त कर सकते हैं। इससे भुगतान में देरी की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने उद्यमियों से डिजिटल मंचों और सरकारी खरीद से जुड़ी योजनाओं की नियमित जानकारी लेने की अपील की।

एमएसएमई विकास कार्यालय, कानपुर के निदेशक वीके वर्मा ने बताया कि सरकारी खरीद में एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 प्रतिशत खरीद का लक्ष्य निर्धारित है। विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा एमएसएमई से खरीद किए जाने से छोटे उद्यमों के लिए बड़े कारोबारी अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने उद्यमियों से वेंडर पंजीकरण और सरकारी खरीद की प्रक्रिया को समझकर इन अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया।जेम के उत्तर प्रदेश राज्य नोडल एवं डिप्टी सीईओ कृष्ण मुरारी ने बताया कि वर्ष 2017 में जेम के शुरू होने के बाद से अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपये की खरीद हो चुकी है। इसमें एमएसएमई की हिस्सेदारी करीब 45 प्रतिशत यानी लगभग नौ लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी करीब एक लाख करोड़ रुपये की खरीद की गई है। उनके अनुसार करीब 25 हजार नए वेंडर पंजीकृत हुए हैं और एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।रेलवे अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के कार्यकारी निदेशक स्टोर्स अकमल वदूद ने कहा कि लखनऊ और आसपास का रेलवे तंत्र एमएसएमई के लिए व्यापक कारोबारी अवसर उपलब्ध कराता है। रायबरेली स्थित आधुनिक कोच कारखाने में करीब 7 से 8 हजार करोड़ रुपये की खरीद होती है। उन्होंने एमएसएमई उद्यमियों से मशीनरी और संयंत्र उपकरणों के क्षेत्र में विनिर्माण के अवसर तलाशने पर जोर दिया।

संक्षेप

मारपीट में राजमिस्त्री की मौत, दो आरोपी हिरासत में

लखनऊ। सरोजनीनगर थाना क्षेत्र के अमौसी में मकान बनाने के औजार और अन्य सामान गायब होने के विवाद में हुई मारपीट के बाद एक राजमिस्त्री की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, मृतक आशीष कुमार द्विवेदी (30) मूल रूप से ग्राम टेमौं, थाना रामसनेहीघाट, बाराबंकी का रहने वाला था और वर्तमान में अमौसी में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। 19 अगस्त को करीब तीन बजे मकान बनाने के औजार और कुछ अन्य सामान गायब होने की बात को लेकर उसका फूलचंद्र श्रीवास्तव (42) और कल्लू उर्फ श्यामलाल रावत (47) से विवाद हो गया।विवाद के दौरान हुई मारपीट में आशीष को चोटें आईं। उसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनीनगर में कराया गया था। 20 अगस्त की सुबह करीब नौ बजे आशीष की उसके घर पर मौत हो गई।सूचना मिलने पर सरोजनीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू की। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना सरोजनीनगर में मु0अ0सं0 320/2026, धारा 105, 115(2) और 352 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

डीसीएम की टक्कर से कांवड़िये की मौत, साथी घायल

लखनऊ। इटौंजा थाना क्षेत्र में सीतापुर-लखनऊ हाईवे पर गुरुवार को अज्ञात डीसीएम की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक कांवड़िये की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और अज्ञात डीसीएम की तलाश शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, 20 अगस्त को करीब 3:30 बजे मोटरसाइकिल संख्या यूपी32 डीए 5383 पर सवार सत्यम गुप्ता (17) पुत्र राकेश गुप्ता, निवासी कुर्सी हिरोरा, थाना संदना, सीतापुर और शोभित गुप्ता (18) पुत्र आशीष कुमार, निवासी पलटूपुर, थाना घूंघटेर, बाराबंकी, सीतापुर से लखनऊ की ओर जा रहे थे।इटौंजा थाना क्षेत्र में सीतापुर-लखनऊ हाईवे पर लाडली होटल के सामने एक अज्ञात डीसीएम वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए रामसागर मिश्र 100 शैय्या अस्पताल, साढ़ामऊ, बीकेटी पहुंचाया।अस्पताल में चिकित्सकों ने सत्यम गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। वहीं शोभित गुप्ता को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ रेफर कर दिया गया। इटौंजा पुलिस ने मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू, लखनऊ भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस हादसे में शामिल अज्ञात डीसीएम वाहन की तलाश कर रही है और मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के मुताबिक, वर्तमान में यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है और घटनास्थल पर कानून-व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या नहीं है।

बिजनौर पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

लखनऊ। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिजनौर थाना पुलिस ने अवैध तमंचा लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।पुलिस के अनुसार, उपनिरीक्षक आनंद प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ बिजनौर चौराहे से कस्बा बिजनौर की ओर पैदल गश्त कर रहे थे। बिजनौर बाजार के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गोलू होटल के सामने से नक्श सिटी जाने वाले मार्ग पर एक युवक तमंचा लेकर घूम रहा है।सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल दबिश देकर रास्ते पर तमंचा लेकर घूम रहे युवक को घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।गिरफ्तार आरोपी की पहचान हुमेद उर्फ हुमैर (26) पुत्र स्वर्गीय सगीर, निवासी घसियारी मोहल्ला, कस्बा व थाना बिजनौर, लखनऊ के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना बिजनौर में मु0अ0सं0 223/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को 20 अगस्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया।पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि करीब डेढ़ वर्ष पहले उसे यह तमंचा जंगल में पड़ा मिला था। इसके बाद उसने तमंचे को अपने पास रख लिया और कभी-कभी शौकिया तौर पर इसे लेकर घूमता तथा लोगों को डराता-धमकाता था।

पीड़ितों और बच्चों से संवेदनशील संवाद के लिए 68 रिक्रूट आरक्षियों को दिया गया प्रशिक्षण

लखनऊ। समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और समावेशी पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कमिश्नरेट लखनऊ में वर्ष 2025 बैच के रिक्रूट आरक्षियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। 20 अगस्त को रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित संगोष्ठी सदन में आयोजित कार्यशाला का विषय "पीड़ितों एवं बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व संवेदनशील संवाद कैसे स्थापित किया जाए" रहा।उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के क्रम में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमिश्नरेट लखनऊ के सभी थानों से वर्ष 2025 बैच के 68 रिक्रूट आरक्षियों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य नवआरक्षियों को संवेदनशील, सजग और प्रभावी प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले पुलिसकर्मी के रूप में तैयार करना रहा।प्रशिक्षण सत्र में यूनिसेफ की डिविजनल कंसल्टेंट रिजवाना परवीन ने प्रतिभागियों को पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने के व्यवहारिक तरीकों की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि घटनास्थल अथवा थाने पर पहुंचने के बाद पीड़ित की बात धैर्यपूर्वक सुनना, उसकी भावनात्मक स्थिति को समझना और उसे आवश्यक सहयोग एवं सुरक्षा का भरोसा दिलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।कार्यशाला में संवाद कौशल और व्यवहारिक विकास के साथ महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े विभिन्न कानूनों और प्रावधानों की जानकारी दी गई। इनमें घरेलू हिंसा से संबंधित कानून, किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम प्रमुख रहे।

अखिलेश यादव के वार पर जयंत चौधरी का संयमित पलटवार, पश्चिमी यूपी की राजनीति में नया उबाल

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का नाम लिए बिना ऐसा तंज कसा है जिसकी गूंज सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान तक पहुंच गई। अखिलेश ने कहा, "कहां-कहां से आ गए थे, चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी..."। दरअसल अखिलेश ने अपने इस बयान के जरिये पुराने साथी को राजनीति में आगे बढ़ाने का दावा किया और फिर साथी द्वारा उन्हें छोड़ देने पर अपनी शिकायत दर्ज कराई लेकिन इस दौरान उनके जो तेवर रहे उसने पश्चिमी यूपी की सियासत को गर्मा दिया है। रालोद कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आये हैं और अखिलेश यादव के पुतले फूंक रहे हैं।

यही नहीं, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने भी अखिलेश पर पलटवार करते हुए दर्शा दिया है कि एक्शन का रिएक्शन तत्काल होगा। हालांकि अखिलेश के तंज पर जयंत चौधरी ने पलटवार तल्खी की बजाय बेहद नपे-तुले अंदाज में किया। उन्होंने कहा, "वो अपनी बात कहें तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी... इस तरह की बयानबाजी से सोचने को मजबूर हो रहे हैं।" जयंत ने आगे कहा, "लोकतंत्र है, यहां जनता सबको बनाती है और सबको बिगाड़ती है।" जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश उन्हें इतना क्यों याद कर रहे हैं, तो उन्होंने गेंद वापस अखिलेश के पाले में डालते हुए कहा, "ये तो आप लोग उनसे जाकर पूछिए।"

दरअसल, यह सिर्फ दो नेताओं की निजी राजनीतिक नोकझोंक नहीं है। इसके पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदलते जातीय और गठबंधन समीकरण की पूरी पटकथा पढ़ी जा सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन में जाट-मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश साफ दिखाई दी थी। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने में भी भूमिका निभाई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री और जयंत के दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद रालोद ने एनडीए का दामन थाम लिया। अब जयंत भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा हैं और केंद्र सरकार में राज्यमंत्री हैं। यही बदलाव अखिलेश के मौजूदा हमले को राजनीतिक धार देता है। सपा प्रमुख लगातार पीडीए यानि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में हैं।

पश्चिमी यूपी में उनकी चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यहां सपा का पारंपरिक मुस्लिम-यादव आधार पूर्वांचल या मध्य यूपी की तरह निर्णायक नहीं रहा है। ऐसे में गुर्जर, दलित, अन्य पिछड़ी जातियों और गैर-जाट मतदाताओं को जोड़ना सपा की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। जयंत चौधरी का रालोद इस गणित में छोटी पार्टी जरूर है, लेकिन पश्चिमी यूपी में उसका प्रभाव उसके चुनावी आंकड़ों से कहीं ज्यादा राजनीतिक वजन रखता है। जाट समुदाय में चौधरी चरण सिंह की विरासत और रालोद की पकड़ अब भी गठबंधन राजनीति के लिए अहम है। भाजपा के साथ जयंत की मौजूदगी एनडीए को पश्चिमी यूपी में जाट समर्थन को साधने का अतिरिक्त आधार देती है। यही कारण है कि अखिलेश का "चवन्नी" वाला तंज महज पुरानी दोस्ती का हिसाब नहीं, बल्कि नए सामाजिक समीकरणों की जंग भी माना जा रहा है।

दिलचस्प यह है कि अखिलेश ने हाल में अपने नेताओं-कार्यकर्ताओं को चुनावी समय में सोच-समझकर बयान देने की नसीहत दी थी, ताकि भाजपा को कोई राजनीतिक लाभ न मिले। इसके तुरंत बाद जयंत पर निशाना साधना बताता है कि सियासी प्राथमिकताएं कभी-कभी रणनीतिक संयम पर भारी पड़ जाती हैं।

उधर, जयंत ने तीखा पलटवार करने की बजाय संयम चुना। शायद इसलिए कि वह अखिलेश के बनाए जाट बनाम गैर-जाट नैरेटिव में फंसना नहीं चाहते। उनकी सौम्य प्रतिक्रिया का संदेश भी उतना ही राजनीतिक है। इसका अर्थ यह है कि रालोद अब सपा के साथ नहीं बल्कि एनडीए के साथ ही अपना भविष्य देख रहा है।

बहरहाल, "चवन्नी" और "रुपया" की यह लड़ाई असल में पश्चिमी यूपी की उस सियासी तिजोरी की लड़ाई है, जिसकी चाबी जाट, मुस्लिम, दलित, गुर्जर और अन्य पिछड़े मतदाताओं के हाथ में है। देखा जाये तो चुनावी राजनीति में सवाल यह नहीं कि किसने किसे रुपया बनाया; असली सवाल यह है कि जनता की नजर में अब कौन कितने का है।

छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति परंपरा व आस्था से जुड़ा है हरेली तिहार

हरेली पर्व के दिन पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए औषधियुक्त आटे की लोंदी खिलाई जाती है। गांव में यादव समाज के लोग वनांचल जाकर कंदमूल लाकर हरेली के दिन किसानों को पशुओं के लिए वनौषधि उपलब्ध कराते हैं।

छगन लाल लोन्हारे

प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गांव, गरीब और किसान सरकार की पहली प्राथमिकता में हैं। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की इन ढाई साल के अवधि में किसानों के हित में लिए गए नीतिगत फैसलों से खेती किसानी को नया संबल मिला है। बीते खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से समर्थन मूल्य पर 141.05 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार का विशेष महत्व है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्यौहार परंपरागत रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती-किसानी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी पूजन होता है। गांव में बच्चे और युवा गेड़ी का आनंद लेते हैं। इस त्यौहार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक पर्वों की महत्ता भी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी के बिना हरेली तिहार अधूरा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रूपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदीकर न सिर्फ किसानों को मान बढ़ाया, बल्कि किसानों को उन्नति की ओर ले जाने में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। साथ ही किसानों के खाते में रमन सरकार के पिछले दो वर्ष का बकाया धान के बोनस 3716.38 करोड़ रूपए अंतरित कर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि भारत गांवों में बसता है। जब किसान खुशहाल होंगे तो प्रदेश का व्यापार, उद्योग बढ़ेगा।

परंपरा के अनुसार वर्षों से छत्तीसगढ़ के गांव में अक्सर हरेली तिहार के पहले बढ़ई के घर में गेड़ी का ऑर्डर रहता था और बच्चों की जिद पर अभिभावक जैसे-तैसे गेड़ी भी बनाया करते थे। हरेली तिहार के दिन सुबह से तालाब के पनघट में किसान परिवार, बड़े बजुर्ग बच्चे सभी अपने गाय, बैल, बछड़े को नहलाते हैं और खेती-किसानी, औजार, हल (नांगर), कुदाली, फावड़ा, गैंती को साफ कर घर के आंगन में मुरूम बिछाकर पूजा के लिए सजाते हैं। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ के चीला का भोग लगाया जाता है। अपने-अपने घरों में अराध्य देवी-देवताओं की साथ पूजा करते हैं। गांवों के गुड़ी में ठाकुरदेव की पूजा की जाती है।

हरेली पर्व के दिन पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए औषधियुक्त आटे की लोंदी खिलाई जाती है। गांव में यादव समाज के लोग वनांचल जाकर कंदमूल लाकर हरेली के दिन किसानों को पशुओं के लिए वनौषधि उपलब्ध कराते हैं। गांव के सहाड़ादेव अथवा ठाकुरदेव के पास यादव समाज के लोग जंगल से लाई गई जड़ी-बूटी उबाल कर किसानों को देते हैं। इसके बदले किसानों द्वारा चावल, दाल आदि उपहार में यादवों को भेंट करने की परंपरा रही हैं।

सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है। हरेली का आशय हरियाली ही है। वर्षा ऋतु में धरती हरा चादर ओढ़ लेती है। वातावरण चारों ओर हरा-भरा नजर आने लगता है। हरेली पर्व आते तक खरीफ फसल आदि की खेती-किसानी का कार्य लगभग हो जाता है। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धोकर, धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ का चीला भोग लगाया जाता है। गांव के ठाकुर देव की पूजा की जाती है और उनको नारियल अर्पण किया जाता है।

हरेली तिहार के साथ गेड़ी चढ़ने की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी परिवारों द्वारा गेड़ी का निर्माण किया जाता है। परिवार के बच्चे और युवा गेड़ी का जमकर आनंद लेते है। गेड़ी बांस से बनाई जाती है। दो बांस में बराबर दूरी पर कील लगाई जाती है। एक और बांस के टुकड़ों को बीच से फाड़कर उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। उसे नारियल रस्सी से बांधक़र दो पउआ बनाया जाता है। यह पउआ असल में पैर दान होता है जिसे लंबाई में पहले कांटे गए दो बांसों में लगाई गई कील के ऊपर बांध दिया जाता है। गेड़ी पर चलते समय रच-रच की ध्वनि निकलती हैं, जो वातावरण को और आनंददायक बना देती है। इसलिए किसान भाई इस दिन पशुधन आदि को नहला-धुला कर पूजा करते हैं। गेहूं आटे को गूंथ कर गोल-गोल बनाकर अरंडी या खम्हार पेड़ के पत्ते में लपेटकर गोधन को औषधि खिलाते हैं। ताकि गोधन को रोगों से बचाया जा सके। गांव में पौनी-पसारी जैसे राऊत, लोहार व बैगा हर घर के दरवाजे पर नीम की डाली खोंचते हैं। गांव में लोहार अनिष्ट की आशंका को दूर करने के लिए चौखट में कील लगाते हैं। यह परम्परा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है। पिहले के दशक में गांव में बारिश के समय कीचड़ आदि हो जाता था उस समय गेड़ी से गली का भ्रमण करने का अपना अलग ही आनंद रहता था। गांव-गांव में गली कांक्रीटीकरण से अब कीचड़ की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। हरेली के दिन गृहणियां अपने चूल्हे-चौके में कई प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाती है। किसान अपने खेती-किसानी के उपयोग में आने वाले औजार नांगर, कोपर, दतारी, टंगिया, बसुला, कुदारी, सब्बल, गैती आदि की पूजा कर छत्तीसगढ़ी व्यंजन गुलगुल भजिया व गुड़हा चीला का भोग लगाते हैं। इसके अलावा गेड़ी की पूजा भी की जाती है। शाम को युवा वर्ग, बच्चे गांव के गली में नारियल फेंक और गांव के खेल मैदान में कबड्डी आदि कई तरह के खेल खेलते हैं। बहु-बेटियां नए वस्त्र धारण कर सावन झूला, बिल्लस, खो-खो, फुगड़ी आदि खेल का आनंद लेती हैं।

हरेली तिहार सामाजिक समरसता का प्रतीक है यह केवल धार्मिक या कृषि पर्व नहीं है यह समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ने का माध्यम है। गांव के लोग मिल-जुलकर पूजा और कार्यक्रमों का आयोजन करते है। इस दिन परिवार में सुख-समृद्धि की कामना के साथ ही प्रकृति और पशुधन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है।

लेखक संयुक्त संचालक जनसंपर्क हैं

व्यंग्य

यथार्थ से टकराती कथाएं

हकीकत से कटे नैरेटिव्स का अपना जीवनकाल होता है। जब उनका सामना विपरीत होते जमीनी हालात से होता है, तो उनमें दरारें पड़ने लगती हैं। ज़ेन-ज़ी का तेवर उन्हीं हालात का नतीजा है।

भारत का राजनीतिक विमर्श काफी पहले शालीनता की हदें तोड़ चुका है, इसलिए इसमें नए अपशब्दों के जुड़ने पर शायद ही किसी को एतराज होता है। तीखे ध्रुवीकरण की मौजूदा सूरत में किसी नेता की टिप्पणियों को गरिमा-विहीन या मर्यादा के खिलाफ बता कर उसे घेरने की रणनीति का विरोधी खेमों पर अब कोई असर नहीं होता। कई वर्षों तक इस नई स्थिति का लाभ भाजपा ने उठाया। भाजपा नेताओं को लेकर कुछ हलकों से तब भी ऐसे शब्द बोले जाते थे, लेकिन तब कथानक पर भाजपा इकॉ-सिस्टम का इतना दबदबा था, वे शब्द बोलने वाले को ही भारी पड़ जाते थे। लेकिन यह बदले माहौल का ही संकेत है कि ऐसे लफ्ज़ अब जनमत के एक बड़े हिस्से में नया राजनीतिक कथानक गढ़ने का काम करने लगे हैं।

भाजपा काफी समय तक विपक्षी नेताओं को प्रहसन-पात्र के रूप में पेश सियासी फायदे उठाती रही, मगर अब सोशल मीडिया- खासकर रील्स के इस्तेमाल से वैसी ही छवि उनके शीर्ष नेताओं को पेश की जा रही है, जिसे एक बड़ा श्रोता वर्ग मिल रहा है। बेशक, यह स्थिति लाने में ज़ेन-ज़ी के आंदोलनों ने बड़ी भूमिका निभाई है। भाजपा के सामने सवाल खड़ा है कि कहानी ऐसे क्यों पलटने लगी है? वे आत्म-मंथन करें, तो शायद उन्हें आभास होगा कि यथार्थ से कटे कथानकों का अपना जीवनकाल होता है। जब उनका सामना विपरीत होते जमीनी हालात से होता है, तो उनमें दरारें पड़ने लगती हैं।

ज़ेन-ज़ी का तेवर उन्हीं हालात का नतीजा है। हिंदुत्व की पहचान के साथ 'विश्व गुरुÓ की हैसियत दिलाने के वादों से वह छली गई महसूस कर रही है, तो उसकी वजहें हैं। ये पीढ़ी 'मेक इन इंडियाÓ, 'नया भारतÓ, 'देश बदल रहा हैÓ, 'अमृत कालÓ, 'विकसित भारतÓ जैसे नारों को सुनते हुए जब बड़ी हुई, तो उसने पाया कि असल में उसके पास आगे बढ़ने के पहले जितने अवसर भी उपलब्ध नहीं हैं। तो वह हिसाब मांग रही है। इसका जवाब 'सप्तधाराÓ जैसे नए नैटेरिव गढ़ कर नहीं दिया जा सकता। ना ही 'दिमागी नक्सलियोंÓ को अलग-थलग करने जैसे एलान नई परिस्थितियों में अपेक्षित भय पैदा कर सकेंगे।

ब्लॉग

आधारभूत चुनौतियों से उन्नत विषयों तक – स्वतंत्रता दिवस भाषणों के जरिए भारत के बदलाव की यात्रा

पिछले एक दशक में भारत ने कितनी दूरी तय की है, इसे मापने का एक सरल तरीका है: प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषणों को सुनना। मोदी सरकार के शुरुआती वर्षों में भाषण उन समस्याओं पर केंद्रित होते थे जिन्हें आज हम सामान्य मान सकते हैं: शौचालय, बिजली, गरीबी, सड़कें, बैंक खाते और उर्वरक की कमी। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने इन पर बात की, तो उनके लहजे में एक तत्परता थी। चुनौती यह थी कि जो टूटा हुआ है उसे ठीक किया जाए और जो छूट गए हैं उन तक पहुंचा जाए।

वर्षों के दौरान, उनकी शब्दावली में बदलाव आने लगा। बातचीत पहुंच से आकांक्षा की ओर, कमियों को दूर करने से क्षमताओं के निर्माण की ओर, और तात्कालिक समस्याओं को हल करने से ऐसी प्रणालियां बनाने की ओर बढ़ी जो भारत की पहचान को फिर से उन समस्याओं से न बांध सकें।

शायद यही कारण है कि लाल किले से दिए गए उनके संबोधनों की अवधि और उनका दायरा अपने आप में एक अलग पहचान बन गया है।

जिस प्रधानमंत्री का कार्य जीवन अथक परिश्रम के लिए जाना जाता है, उनके द्वारा लाल किले से देश की यात्रा को प्रस्तुत करने में समर्पित समय बहुत कुछ बयां करता है। ये केवल वार्षिक भाषण नहीं हैं; यदि इन्हें एक साथ पढ़ा जाए, तो ये देश के रूपांतरण के एक चलते-फिरते रिकॉर्ड जैसे प्रतीत होते हैं।

1. शौचालय ? सेमीकंडक्टर

2014: क्या हम अपनी माताओं और बहनों की गरिमा के लिए शौचालय की व्यवस्था भी नहीं कर सकते?

2026: आज की डिजिटल दुनिया और तकनीक-संचालित युग में, हम चिप के महत्व को समझते हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, चिकित्सा उपकरण हों या परिवहन प्रणाली, चिप्स हर जगह अनिवार्य हैं। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां चिप्स के बिना पूरी व्यवस्था ठप हो सकती है। यही कारण है कि भारत ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपनी सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमता स्थापित करना शुरू कर दिया है।

2. ग्रामीण सड़कें ? उपग्रह ? मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन ? एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग

2016: हमारे देश में ग्रामीण सड़कें एक शाश्वत मुद्दा हैं। प्रत्येक ग्रामीण नागरिक पक्की सड़कों की इच्छा रखता है।

2018: हमारे वैज्ञानिकों ने एक साथ 100 से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित किए, जिससे पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई।

2024: मैंने देखा है कि चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद हमारे स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि का एक नया माहौल बना है।

2025: हम अंतरिक्ष में अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने दम पर अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

2026: आज एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस, रोबोटिक्स और डेटा सेंटर का युग है। एक बिल्कुल नया क्षेत्र खुल गया है। उभरती प्रौद्योगिकियां हमें हर पल चुनौती दे रही हैं। इसलिए, हमें अपने देश को केवल दुनिया का बाजार नहीं बनाना है; हमें नवाचार का केंद्र बनना होगा।

3. गरीबी के खिलाफ लड़ाई

2014: यदि भारत के लोग बिना सरकार की ताकत के, बिना हथियारों के और बिना संसाधनों के भी इतने बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंक सकते हैं, तो दोस्तों, आज समय की मांग है कि गरीबी को मिटाया जाए, क्या हम गरीबी पर विजय नहीं पा सकते? क्या हम गरीबी को हरा नहीं सकते? मेरे 125 करोड़ प्यारे देशवासियो, आइए हम गरीबी मिटाने का, इसके खिलाफ जीतने का संकल्प लें।

2026: विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले केवल 25 करोड़ लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा कवच था... हमने एक दशक के भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया है।

4. महिलाओं की गरिमा से लेकर महिला-नेतृत्व वाले आरक्षण तक

2014: हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। क्या हमें कभी इस बात का दर्द हुआ है कि हमारी माताओं और बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है? क्या महिलाओं की गरिमा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है? गांव की गरीब महिलाएं रात होने का इंतजार करती हैं; जब तक अंधेरा न हो जाए, वे शौच के लिए बाहर नहीं जा सकतीं... क्या हम अपनी माताओं और बहनों की गरिमा के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं कर सकते?

2018: मैं गर्व के साथ भारतीय सशस्त्र बलों की शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिला अधिकारियों की नियुक्ति के लिए स्थायी कमीशन देने की घोषणा करता हूं।

2026: आइए हम उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए आगे आएं और यह सुनिश्चित करें कि हमारी माताओं और बहनों को जल्द से जल्द विधानसभाओं और लोकसभा में 33त्न प्रतिनिधित्व मिले, ताकि वे भारत की नीतियों को आकार देने में योगदान दे सकें। यह समय की मांग है और मैं एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि आएं और इस कार्य में शामिल हों।

5. किसानों को प्राथमिकता देना

2014: लेकिन, कृपया मुझे बताएं कि हमारे किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? किसान साहूकार से कर्ज लेता है, लेकिन कर्ज चुकाने में असमर्थ रहता है। वह अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लेता है, लेकिन चुका नहीं पाता। उसे जिंदगी भर कष्ट सहने पड़ते हैं। वह आत्महत्या का रास्ता चुनता है। ऐसे किसानों के गरीब परिवारों को कौन बचाएगा?

2018: अर्थशास्त्री, किसान संगठन, किसान और साथ ही राजनीतिक दल यह मांग कर रहे थे कि किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूस्क्क) मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर सालों तक बहस हुई, फाइलें इधर-उधर घूमती रहीं, लेकिन बात अटकी रही। आखिरकार हमने फैसला लिया। हमने किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना रूस्क्क देने का साहसिक निर्णय लिया।

2025: पिछले साल मेरे देश के किसानों ने खाद्यान्न उत्पादन में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए... 4 लाख करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है।

2026: हमारे किसानों की पहुंच अब वैश्विक बाजारों तक है। एफटीए के कारण हमें एक बहुत बड़े बाजार तक पहुंच मिल रही है... हमें खेत से निर्यात बाजार की ओर बढ़ना होगा। चाहे हमारा पारंपरिक व्यंजन हो, हमारे मोटे अनाज (श्री अन्न) हों, हमारे मसाले हों, हमारे फल हों या हमारे फूल हों... आज इस एफटीए के कारण हमारे झींगा के निर्यात की संभावना बहुत बढ़ गई है।

6. स्टार्टअप इंडिया

2015: मुझे स्टार्टअप्स को ताकत देनी है और इसलिए, मैं संकल्प लेता हूं कि आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया होगा।

2016: आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए जहां स्टार्टअप शुरू न हों। क्या भारत यह सपना नहीं देख सकता कि वह स्टार्टअप की दुनिया में दुनिया में नंबर एक बने? आज हम उस स्थिति में नहीं हैं।

2026: हमने कई रास्ते खोले हैं; हमने स्टार्टअप सेक्टर खोला है। आपने देखा होगा कि औसतन 28 वर्ष की आयु के युवाओं के नेतृत्व वाले भारत के निजी स्टार्टअप्स ने अपने उपग्रह और रॉकेट लॉन्च किए, जो अपने पहले ही प्रयास में सफल रहे। उन्होंने वास्तव में कुछ उल्लेखनीय हासिल किया है।

7. विनिर्माण/प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता

2014: ...इलेक्ट्रिकल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, आइए, मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर कृषि मूल्य संवर्धन तक आइए, मेक इन इंडिया, कागज हो या प्लास्टिक, आइए, मेक इन इंडिया, उपग्रह हो या पनडुब्बी आइए, मेक इन इंडिया।

2025: ...इसी साल के अंत तक, भारत के लोगों द्वारा भारत में निर्मित मेड इन इंडिया चिप बाजार में उपलब्ध होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर साइबर सुरक्षा तक, दीप टेक से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सब कुछ हमारा अपना होना चाहिए, जिस पर हमारे अपने लोगों की क्षमता केंद्रित हो, हमें दुनिया के सामने उनकी क्षमताओं की ताकत को पेश करना चाहिए।

2026: हमें विनिर्माण क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाना चाहिए; उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ, हमें छोटे घटकों से लेकर बड़े पैमाने के उत्पादों तक सब कुछ बनाने की आवश्यकता है। पूरी वैल्यू चेन हमारी होनी चाहिए और हमें इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमें घटकों के साथ-साथ पूर्ण विनिर्माण की आवश्यकता है, हमें पूर्ण उत्पाद भी चाहिए। डिजाइन से लेकर विनिर्माण तक, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में उभरना होगा।

8. गांव का विद्युतीकरण ? परमाणु ऊर्जा का विस्तार

2015: इन 18,500 गांवों में बिजली के खंभे, बिजली के तार और बिजली पहुंचाने का लक्ष्य अगले 1000 दिनों के भीतर हासिल कर लिया जाएगा।

2026: ऊर्जा सुरक्षा समय की मांग है, और इसलिए, हमने इस दिशा में पहले ही कई कड़े कदम उठाए हैं। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक बड़ा माध्यम परमाणु ऊर्जा है। संसद में शांति (स॥्रहञ्जङ्ख) अधिनियम पारित करके, हमने एक नए लक्ष्य की राह प्रशस्त की है। 2047 तक, हम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। इसी दशक के भीतर, हमने पांच नए परमाणु रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य रखा है।

9. इंटरनेट कनेक्टिविटी

2015: आप कल्पना कर सकते हैं कि गांवों के बच्चों को कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, यदि भारत के सभी गांव ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ जाएं और यदि हम गांवों के हर दूर-दराज के कोने के स्कूलों में दूरस्थ शिक्षा (स्रद्बह्यह्लड्डठ्ठष्द्ग द्गस्रह्वष्ड्डह्लद्बशठ्ठ) देने में सक्षम हों।

2024: हमने वे दिन भी देखे हैं जब हमें 2त्र के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। हम 6त्र के लिए पहले से ही मिशन मोड में काम कर रहे हैं और हम अपनी प्रगति से दुनिया को चौंका देंगे।

2026: इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं की संख्या लगभग चार गुना बढ़ गई है।

जेन अल्फा से दोस्त की तरह बात करेंगे यूपी के अफसर, सरकार ने युवाओं के लिए बनाया बड़ा प्लान

आर्यावर्त संवाददाता

उत्तर प्रदेश राज्य के अलग-अलग हिस्सों से Gen Alfa के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आईं। ऐसे में इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार का रवैया बदला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, जहां भी प्रदर्शन होगा वहां युवा अफसर बातचीत के लिए जाएंगे। अफसर Gen Alfa से दोस्त की तरह बातचीत करेंगे। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार की तरफ से यूथ पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसे जल्द ही सामने लाया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार बना युवा आयोग बना सकती है। इस आयोग में छात्रों के प्रतिनिधि होंगे जो अपनी मांगों और मुश्किलों को लेकर अपनी बात रखेंगे। सभी रिक्त पदों पर भर्ती करने की भी तैयारी है। यूपी पुलिस से भी युवाओं के लिए आदेश आ सकता है। युवा प्रदर्शन करेंगे तो नहीं होगा लाठीचार्ज उन्हें बातचीत के जरिए समझाया जाएगा।

पिछले एक महीने में उत्तर प्रदेश भर के छात्रों ने स्कूल से जुड़ी अपनी शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। लखनऊ और उन्नाव में सड़कें जाम कीं, हमीरपुर में कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और कन्नौज में खुद को हॉस्टल के अंदर बंद कर लिया, जब तक कि अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी।

Gen Alfa की मांगें बुनियादी चीजों से जुड़ी हुई थीं। उन्होंने शिक्षक, बेहतर खाना, पीने का पानी, ठीक से चलने वाले पंखे, साफ-सुथरा कैंपस और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग की। इनमें से तीन विरोध प्रदर्शन, लखनऊ और उन्नाव के सर्वोदय आवासीय स्कूलों में, कुछ ही दिनों के अंतराल पर हुए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे ऐसे सभी 103 स्कूलों के निरीक्षण का आदेश दिया।

क्या हैं समस्याएं?

छात्रों ने आरोप लगाया कि शिक्षकों की कमी है, खाना खराब क्वालिटी का है, पीने का पानी पर्याप्त नहीं है, शिक्षकों का व्यवहार ठीक नहीं है और साफ़-सफाई की भी समस्या है। पुलिस, समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को विरोध प्रदर्शन वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश की। लगभग आधे घंटे बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुशील कुमार गौड़ ने बताया कि छात्र कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

कादीपुर में पांच दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण का शुभारंभ

आर्यावर्त संवाददाता

कादीपुर/सुलतानपुर। ब्लॉक संसाधन केंद्र कादीपुर में पांच दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी पूजा पाठक ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने शिक्षकों से प्रशिक्षण को गंभीरता से प्राप्त कर विद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की। प्रशिक्षण में भाषा एवं गणित के आधारभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान पर 50-50 के बैच में कुल 100 शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं। संदर्भदाता एआरपी नीतीश पांडेय, राजेश कुमार, बृजेश सिंह तथा केआरपी चंद्रपाल राजभर व विकास तिवारी ने शिक्षकों को विभिन्न गतिविधियों और शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिया। इसका उद्देश्य बच्चों के भाषा व गणितीय कौशल को मजबूत करना है।

स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त, सात बच्चे घायल

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के सुजानगंज मार्ग पर उकनी गांव के पास गुरुवार को तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने ओवरटेक करने के दौरान स्कूल वैन में साइड मार दी। टक्कर लगते ही डीआरएम पब्लिक स्कूल मधुपुर की वैन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के समय वैन में करीब एक दर्जन बच्चे सवार थे। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।हादसे में सात बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई अन्य बच्चों को भी चोटें आईं। आसपास के ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। सूचना पर मुंगराबादशाहपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य में सहयोग किया। सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी सुजानगंज ले जाया गया।घायलों में आदित्य यादव (11), सिद्धार्थ यादव

(10), प्रभाष यादव (12), अनिरुद्ध यादव (10), आर्यन यादव (10), आकाश तिवारी (10) और शिवम तिवारी (8) शामिल हैं। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सिद्धार्थ यादव, प्रभाष यादव और आदित्य यादव की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष निरीक्षक चौकी प्रभारी और क्षेत्राधिकारी प्रतिमा वर्मा मौके पर पहुंचीं। घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे की खबर मिलते ही बच्चों के अभिभावक और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए।बताया गया कि स्कूल वैन मुंगराबादशाहपुर की ओर से सुजानगंज जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस के चालक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान बस ने वैन में साइड मार दी, जिससे वैन सड़क पर पलट गई। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने बताया कि सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका उपचार चल रहा है। तीन बच्चों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। तीनों बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर है।

20 रुपये से भी कम एक जान की कीमत? गाजियाबाद में युवक की हत्या, अगले दिन पुलिस से भी भिड़ा आरोपी, मुठभेड़ में घायल

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से इंसानियत और बदमिजाजी को शर्मसार करने वाली एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शालीमार गार्डन इलाके में महज 20 रुपये के मामूली लेनदेन को लेकर शुरू हुआ कहासुनी का विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक की जान चली गई। हत्या के बाद भाग रहे आरोपी को पुलिस ने अगले ही दिन एक भीषण मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह पूरी वारदात 19 अगस्त की है। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विक्रम एन्क्लेव इलाके में 23 वर्षीय मुश्ताक और 20 वर्षीय समीर उर्फ गट्टू के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि

दोनों के बीच झगड़ा सिर्फ 20 रुपये को लेकर हुआ था। मामूली कहासुनी में गुस्साया समीर अपना आपा खो बैठा और उसने मुश्ताक पर चाकू से हमला कर दिया।

पेट और शरीर पर चाकू लगने से घायल मुश्ताक को तुरंत राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत होने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुश्ताक की मौत की खबर मिलते ही पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।

घेराबंदी देख चलाई गोली: सुनसान गली में मुठभेड़

हत्या के बाद से ही आरोपी समीर फरार चल रहा था। पुलिस टीम को सूचना मिली कि वह शालीमार गार्डन इलाके के आसपास ही छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। चेकिंग के दौरान डीएलएफ रोड की तरफ से एक युवक KTM बाइक पर आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो उसने बाइक मोड़ ली और तेजी से टेलीफोन एक्सचेंज वाली सुनसान गली की तरफ भागने लगा। जब पुलिस टीम ने पीछा कर उसे चारों तरफ से घेर लिया, तो खुद को फंसता देख आरोपी समीर ने पुलिस टीम पर सीधे तमंचे से फायर झोंक दिया और भागने का प्रयास किया।

जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली

पुलिसकर्मियों ने खुद का बचाव करते हुए तुरंत नियंत्रित जवाबी फायरिंग की। इस कार्रवाई में एक गोली आरोपी समीर के बाएं पैर में जा लगी। पैर में गोली लगते ही वह बाइक सहित गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने घायल आरोपी को तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। आरोपी की पहचान समीर उर्फ गट्टू के रूप में हुई है, जो दिल्ली के सीमापुरी इलाके का निवासी बताया जा रहा है।

अवैध तमंचा और चोरी की बाइक बरामद

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा व इस्तेमाल किए गए कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जांच में पता चला है कि आरोपी समीर के खिलाफ शालीमार गार्डन थाने में पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है ताकि चोरी की बाइक के स्रोत और अन्य वारदातों में उसकी संलिप्तता का पता लगाया जा सके।

आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की मौत पर गरमाई सियासत, हकीकत जानने अंबेडकरनगर पहुंचेगा सपा का डेलिगेशन, सौंपेगा रिपोर्ट

आर्यावर्त संवाददाता

अंबेडकरनगर। अंबेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में समाजवादी पार्टी ने प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। सपा का प्रतिनिधिमंडल आज 20 अगस्त को ग्राम रुढ़ा पहुंचेगा। सपा डेलिगेशन शोकाकुल परिवार से मुलाकात करेगा। घटना की जानकारी लेने के बाद प्रदेश कार्यालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी की।

डेलिगेशन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय समेत कई नेता शामिल हैं। जलालपुर विधायक राकेश पांडेय समेत स्थानीय सपा नेता भी रहेंगे मौजूद। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल में विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारियों को शामिल किया गया

है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि सपा ने घटना की जानकारी लेने का निर्णय लिया है। कल यानी बुधवार को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी गए थे।

अजय राय कल पहुंचे थे आशुतोष मिश्रा के घर

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को आशुतोष मिश्रा के आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की थी। IPS आशुतोष मिश्रा ने अपनी मां की परिस्थितियों में मौत को लेकर मंगलवार को पहली बार इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने घटना से संबंधित अपुष्ट सूचनाओं और अफवाहों पर नाराजगी व्यक्त की। मिश्रा ने निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस अधिकारियों पर भरोसा जताया। आईपीएस की मां की मौत को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था यूपी में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण! उनके इस बयान के बाद यूपी की सियासत काफी गरमा गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

शनिवार रात संदिग्ध हालात में हुई थी मौत

बता दें कि लखनऊ में पुलिस आवास निर्माण प्रभारी पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की बुजुर्ग मां इंद्रा देवी की शनिवार रात को संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। शुरुआती में ये बताया गया था कि उनकी हत्या की गई है। मगर पोस्टमार्टम में कुछ और ही जानकारी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका था। जानकारी के मुताबिक, उनका शव घर के अंदर बेड पर पड़ा मिला। बदमाशों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था और सोने की चेन, कंगन, कुंडल, अंगूठी समेत अन्य जेवरात लूट लिए। वारदात के बाद कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया।

राजीव गांधी जयंती पर कांग्रेसियों ने किया नमन आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान को किया याद

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्व. राजीव गांधी की जयंती पर गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा, शहर अध्यक्ष शकील अंसारी समेत पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद आयोजित संगोष्ठी में राजीव गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माण के दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, कंप्यूटर और दूरसंचार के क्षेत्र को बढ़ावा देकर देश की विकास यात्रा को नई दिशा दी। पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत कर उन्होंने गांवों तक लोकतांत्रिक भागीदारी को सशक्त बनाने का काम किया। युवाओं को राजनीति और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में हरीश त्रिपाठी, सलाउद्दीन हाशमी, रणजीत सिंह सलूजा, राहुल त्रिपाठी, सुरेंद्र शुक्ला, सुब्रत सिंह सनी, मनोज कुमार तिवारी, सुरेश चंद मिश्रा, वरुण मिश्र, समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।

हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद कार्यक्रम स्थल और मंच के गंगाजल से शुद्धिकरण किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। इसके बाद कार्यकर्ता विकास भवन स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां सत्याग्रह कर विरोध जताया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि किसी राजनीतिक कार्यक्रम के बाद मंच और स्थल का शुद्धिकरण किया जाना लोकतांत्रिक मर्यादाओं और सामाजिक सद्भाव के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी मानसिकता समाज में जातिगत भेदभाव की दीवार खड़ी करती है। राणा ने कहा कि कांग्रेस संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे के मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। पूर्व राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राजेश तिवारी ने भी घटना को लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह किसी एक दल का नहीं, बल्कि समानता में विश्वास रखने वाले लोगों के सम्मान का सवाल है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आयुषी मर्डर केस : मां-बाप को आजीवन कारावास

» यमुना एक्सप्रेसवे के पास लाल रंग के ट्रॉली बैग में मिली थी लाश

आर्यावर्त संवाददाता

मथुरा। चार साल पहले एक युवती का शव यमुना एक्सप्रेसवे के लिंक रोड पर ट्रॉली बैग में मिला था। पुलिस पड़ताल में माता-पिता को आरोपी बनाया गया था। बेटी की गोली मारकर हत्या करने वाले माता-पिता को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास और पिता पर सात व मां पर छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया 18 नवंबर 2022 को राया के यमुना एक्सप्रेस के लिंक रोड स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के पास लाल रंग के ट्रॉली बैग में 21 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ। युवती की बाईं छाती में गोली का निशान था। सिर, हाथ और पैरों में चोट के निशान उसके ऊपर हुई बेरहमी की तरफ इशारा कर रहे थे।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज युवती की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए। 21 नवंबर को मृतका की पहचान दिल्ली के बदरपुर मोड़ बंद एक्सटेंशन निवासी 21 वर्षीय आयुषी यादव के रूप में हुई। पुलिस ने हत्याकांड का राजफाश करते हुए बताया कि आयुषी की हत्या उसके पिता नितेश यादव ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर की है।

हत्या के बाद पत्नी ब्रजबाला की मदद से शव को छिपाने के लिए यमुना एक्सप्रेस के लिंक मार्ग पर फेंक दिया। पुलिस ने युवती की मां ब्रजबाला और पिता नितेश यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यहां से दोनों को जेल भेज दिया। कुछ समय बाद दोनों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट में हुई।

सुनवाई के दौरान आरोपितों के अधिवक्ता ने उन्हें निर्दोष साबित करने का काफी प्रयास किया, लेकिन एडीजीसी की दलील, 11 गवाह, साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पिता नितेश यादव पर सात हजार रुपये और मां ब्रजबाला पर छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद बेटी की हत्या करने वाले माता-पिता को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।

कम्प्यूटर क्रांति के जनक थे राजीव गांधी

जौनपुर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन मे सद्भावना दिवस के रुप में मनाया गया। जिलाध्यक्ष डा प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि स्व.राजीव गांधी जी दूरदर्शी सोच के नेता थे, उनके उदार व्यक्तित्व ने पूरी दुनिया में अमिट छाप छोड़ा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष डा प्रमोद कुमार सिंह ने देश के विकास में राजीव गांधी जी के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि सूचना और कंप्यूटर क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी जी ने देश के युवाओं को मताधिकार का प्रयोग और पंचायती राज एक्ट के माध्यम से देश की मुख्य धारा में समाज के हर वर्ग के लोगों को समान अवसर प्रदान करने का क्रांतिकारी काम किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्व. राजीव गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान जयमंगल यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

5 बच्चों की मां प्रेमी संग भागी, पति बोला- लौट आओ वरना जहर खा लूंगा'... तो बोली- खा लो, फिर हुआ ये अंजाम

आर्यावर्त संवाददाता

भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सुरियावां थाना क्षेत्र के कसौड़ा गांव में 5 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पत्नी के जाने और उसके रूखे व्यवहार से आहत होकर 45 वर्षीय पति ने शराब में जहर मिलाकर पी लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने से पहले पति ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि वह अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए हर संभव कोशिश कर चुका था और उसने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।

जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित कसौड़ा गांव निवासी लल्लू गौतम (45 वर्ष) मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। उसके परिवार में वृद्ध पिता अमृतलाल गौतम, मां, छोटा भाई अमरजीत,

पत्नी सोनी और 5 मासूम बच्चे हैं। लल्लू की शादी 20 साल पहले सोनी से हुई थी। दोनों के 5 बच्चे हैं, तीन बेटियां और दो बेटे। बच्चों की उम्र 7 से 16 वर्ष के बीच है। करीब 2 महीने पहले सोनी अपने गांव/क्षेत्र के ही बिपिन राव नामक व्यक्ति के साथ अचानक घर छोड़कर चली गई थी।

लल्लू की 16 साल की बेटी और 12 साल के बेटे ने घटना की आपबीती सुनाते हुए बताया कि मां के जाने के बाद पिता लगातार उससे फोन पर बात करके घर वापस लौटने की गुहार लगा रहे थे। सोनी ने पहले सोमवार को वापस लौटने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं आई। बुधवार को लल्लू ने फिर से फोन कर सोनी से कहा, "अगर तुम वापस नहीं लौटी तो मैं जहर खा लूंगा।" इस पर सोनी ने संवेदनहीनता दिखाते हुए जवाब दिया, "खा लो।" पत्नी के इस जवाब से बेहद दुखी और गुस्से में आकर लल्लू ने शराब में जहर घोला और बच्चों के सामने ही उसे पी लिया।

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम, बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

तबीयत बिगड़ने पर परिजन लल्लू को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) सुरियावां ले गए। हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल भदोही रेफर कर दिया, जहां दोपहर करीब 1 बजे इलाज के दौरान लल्लू ने दम तोड़ दिया। पिता की मौत के बाद 5 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।

डेंगू या स्वाइन फ्लू? हर बुखार एक जैसा नहीं होता, ऐसे पहचानें लक्षणों में फर्क

बारिश के मौसम डेंगू के मामले बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बीमारी और स्वाइन फ्लू के लक्षणों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। एक्सपर्ट से जानें क्या है इनमें फर्क और बचाव के लिए क्या किया जा सकता है?

बारिश का मौसम आते ही डेंगू और स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि दोनों बीमारियों के शुरुआती लक्षण काफी हद तक एक जैसे दिखाई देते हैं। तेज बुखार, शरीर में दर्द और कमजोरी जैसी समस्याओं के कारण मरीज अक्सर यह समझ नहीं पाते कि उन्हें डेंगू हुआ है या स्वाइन फ्लू। कई बार जांच रिपोर्ट आने तक स्थिति साफ नहीं हो पाती।

विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों बीमारियों के फैलने का तरीका बिल्कुल अलग है, इसलिए इनके लक्षणों को समझना और समय पर जांच कराना बेहद जरूरी है। चलिए आपको एक्सपर्ट के जरिए बताते हैं इनमें फर्क...

कैसे फैलता है डेंगू और स्वाइन फ्लू?

डॉ। आशीष चौधरी (एमडी, आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशयलिटी हॉस्पिटल) ने इस बारे में बताया है। डॉ आशीष कहते हैं कि डेंगू एक वायरल बीमारी है, जो एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। यह मच्छर दिन के समय अधिक सक्रिय रहता है और घरों के आसपास जमा साफ पानी में पनपता है। कूलर, गमले, छत पर रखे बर्तन और निर्माण स्थलों पर जमा पानी इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह मानी जाती है।

वहीं, स्वाइन फ्लू एक संक्रामक श्वसन संबंधी बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलती है। भीड़भाड़ वाली जगहों, स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहन में इसके फैलने का खतरा अधिक होता है।

डेंगू के लक्षण क्या हैं?

अचानक तेज बुखार
जोड़ों और मांसपेशियों में तेज दर्द
आंखों के पीछे दर्द
सिरदर्द
त्वचा पर लाल चकत्ते
कमजोरी और थकान
प्लेटलेट्स की संख्या में कमी

डेंगू को कई बार 'हड्डी तोड़ बुखार' भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है।

स्वाइन फ्लू के लक्षण कैसे अलग हैं?

तेज बुखार
गले में खराश
खांसी
नाक बंद होना
शरीर में दर्द
थकान
सांस लेने में परेशानी

इसी वजह से कई लोग इसे सामान्य वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

दोनों बीमारियों की पहचान कैसे होती है?

डॉ आशीष के मुताबिक,डेंगू की पुष्टि के लिए खून की जांच कराई जाती है। वहीं, स्वाइन फ्लू की जांच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाता है। केवल लक्षणों के आधार पर इन दोनों बीमारियों की सही पहचान करना मुश्किल हो सकता है।

लापरवाही पड़ सकती है भारी

अगर डेंगू का समय पर इलाज नहीं किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है और खून बहने जैसी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। दूसरी ओर, स्वाइन फ्लू फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है और निमोनिया या सांस लेने में गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है। बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में इसका खतरा और बढ़ जाता है।

क्या करें?

बारिश के मौसम में बुखार को बिल्कुल भी हल्के में न लें। अगर तेज बुखार के साथ शरीर में दर्द, खांसी, गले में खराश या प्लेटलेट्स में कमी जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर जांच और सही इलाज ही इन दोनों बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।

आइब्रो थ्रेडिंग कराने से हो सकता है ये खतरा, पार्लर जाने से पहले जान लें

आइब्रो को सही शेप देने के लिए थ्रेडिंग महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय ब्यूटी ट्रीटमेंट है। कुछ मिनटों में भौंहों के अतिरिक्त बाल हटाकर चेहरे को साफ और आकर्षक लुक मिल जाता है। हालांकि, थ्रेडिंग को पूरी तरह जोखिम-मुक्त नहीं माना जा सकता। इस प्रक्रिया में बालों को जड़ से निकाला जाता है, जिससे कुछ लोगों की त्वचा हो सकती है।

गलत तकनीक या साफ-सफाई का ध्यान न रखने पर संक्रमण जैसी समस्या भी हो सकती है। ऐसे में पार्लर जाने से पहले कुछ जरूरी सावधानियां जानना बेहद जरूरी है। यहां हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे।

आइब्रो थ्रेडिंग के संभावित साइड इफेक्ट

1. लालिमा और जलन

थ्रेडिंग के बाद आइब्रो के आसपास हल्की लालिमा, जलन या सूजन होना आम हो सकता है। संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में यह परेशानी थोड़ी ज्यादा समय तक रह सकती है।

2. छोटे दाने या फॉलिकुलाइटिस

थ्रेडिंग में बाल जड़ से निकाले जाते हैं, जिससे हेयर फॉलिकल में जलन या सूजन हो सकती है। इसके कारण छोटे लाल दाने, खुजली या मुंहासे जैसे बंप्स नजर आ सकते हैं।

3. संक्रमण का खतरा

अगर थ्रेडिंग के दौरान साफ-सफाई का ध्यान न रखा जाए, तो बैक्टीरिया त्वचा में प्रवेश कर सकते हैं। इससे लालिमा, दर्द, सूजन या पस वाले दाने जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए साफ-सुथरे पार्लर में ही थ्रेडिंग कराएं।

4. त्वचा पर कट या चोट

आंखों के आसपास की त्वचा काफी नाजुक होती है। गलत तरीके या ज्यादा दबाव से थ्रेडिंग कराने पर त्वचा पर खरोंच, हल्का कट या चोट लग सकती है।

5. आइब्रो का शेप बिगड़ना

अगर थ्रेडिंग करने वाला व्यक्ति अनुभवी नहीं है, तो जरूरत से ज्यादा बाल निकल सकते हैं। इससे दोनों आइब्रो का शेप असमान हो सकता है और बालों के दोबारा उगने में भी समय लग सकता है।

थ्रेडिंग से पहले इन बातों का रखें ध्यान

साफ-सफाई का ध्यान रखने वाले अनुभवी व्यक्ति से ही थ्रेडिंग कराएं
हर ग्राहक के लिए साफ और नया धागा इस्तेमाल किया जाना चाहिए
थ्रेडिंग से पहले और बाद में हाथ व त्वचा की स्वच्छता का ध्यान रखें
अगर त्वचा पर पहले से कट, संक्रमण या तेज जलन है तो थ्रेडिंग टाल दें
रेटिनॉल/रेटिनॉइड इस्तेमाल करने वालों को थ्रेडिंग से पहले डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए

कब डॉक्टर से मिलें?

अगर थ्रेडिंग के बाद लगातार सूजन, बढ़ती लालिमा, दर्द, पस वाले दाने या संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई दें, तो त्वचा विशेषज्ञ से संपर्क करें। फॉलिकुलाइटिस में कभी-कभी चिकित्सकीय उपचार की जरूरत पड़ सकती है।

एक क्लिक में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, फोन बेचने से पहले ये गलती न करें

पुराना फोन बेचने से पहले सिर्फ फोटो और ऐप्स हटाना काफी नहीं है। डेटा का बैकअप लेने के बाद अकाउंट्स, बैंकिंग ऐप्स, सेव पासवर्ड, Bluetooth डिवाइस, SIM और MicroSD कार्ड को सुरक्षित तरीके से हटाएं और आखिर में Factory Reset करें।

आज के समय में स्मार्टफोन बदलना जितना आसान है, पुराने फोन से निजी जानकारी हटाना उतना ही जरूरी है। नया मोबाइल खरीदते ही लोग अक्सर पुराने फोन को एक्सचेंज या बेचने की जल्दी में रहते हैं। इसी जल्दबाजी में अगर फोन में बैंकिंग डिटेल, फोटो, चैट, ईमेल, पासवर्ड या जरूरी दस्तावेज रह जाएं तो आपकी निजी जानकारी गलत हाथों में पहुंच सकती है। इसलिए फोन किसी दूसरे व्यक्ति को देने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं।

पहले जरूरी डेटा का बैकअप लें

फोन साफ करने से पहले अपने जरूरी कॉन्टैक्ट्स, फोटो, वीडियो और दस्तावेजों को सुरक्षित जगह पर सेव कर लें। एंड्रॉयड यूजर्स गूगल ड्राइव और आईफोन यूजर्स iCloud पर बैकअप ले सकते हैं। व्हाट्सएप की चैट का नया बैकअप बनाना भी न भूलें ताकि नए फोन में पुरानी बातचीत सुरक्षित रहे।

सभी अकाउंट्स से निकलें

फोन को सीधे रीसेट करने के बजाय पहले गूगल अकाउंट या एप्पल आईडी को रिमूव या साइन-आउट करें। इसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स से भी लॉगआउट करें। ऐसा न करने पर कुछ मामलों में Factory Reset Protection लॉक की वजह से नए यूजर को फोन सेटअप करने में परेशानी हो सकती है।

बैंकिंग और UPI ऐप्स हटाएं

पुराने फोन में Google Pay, PhonePe, Paytm या YONO SBI जैसे बैंकिंग और पेमेंट ऐप्स हैं तो पहले अपने बैंक अकाउंट को डी-लिंक करें। केवल ऐप अनइंस्टॉल करना काफी नहीं है। पहले ऐप का डेटा और कैशे क्लियर करें और फिर उसे हटाएं।

सेव पासवर्ड भी मिटाएं

क्रोम में सेव किए गए पासवर्ड और ऑटोफिल डिटेल्स भी जांच लें। Password Manager में जाकर सेव पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी और पते जैसी डिटेल्स डिलीट कर दें। स्मार्टवॉच, ईयरबड्स, कार स्टीरियो या स्मार्ट टीवी जैसे डिवाइसों को Bluetooth सेटिंग्स में जाकर Forget Device या Unpair कर दें। इससे पुराने फोन का कनेक्शन नए यूजर के पास नहीं रहेगा।

आखिर में करें Factory Reset

बाकी सभी काम पूरे करने के बाद Settings में जाकर General Management या System के Reset ऑप्शन से Erase All Data चुनें। इससे फोन का डेटा मिट जाएगा और डिवाइस अपनी शुरुआती स्थिति में लौट आएगा। इसके बाद ही फोन को एक्सचेंज या बिक्री के लिए देना बेहतर है।

डिजिटल भुगतान में तेज उछाल के बावजूद भारत में चलन में नकदी बढ़ी : आरबीआई डिप्टी गवर्नर

डिप्टी गवर्नर

भारत में पिछले एक दशक के दौरान डिजिटल भुगतान को अपनाने में तेज वृद्धि के बावजूद चलन में नकदी में कमी नहीं आई है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों, कम आय वाले समूहों, बुजुर्ग आबादी और छोटे कारोबारों में नकदी का इस्तेमाल बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने यह बयान दिया।

डिप्टी गवर्नर ने 13 अगस्त को जकार्ता में बैंक इंडोनेशिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान कहा, डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के कारण व्यक्तिगत लेनदेन में नकदी की हिस्सेदारी घटने के बावजूद, चलन में मुद्रा दोहरे अंकों की दर से बढ़ रही है। इस संयोजन के कारण भविष्य की मांग का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे उत्पादन और वितरण क्षमता की हमारी योजना और जटिल हो जाती है।

उन्होंने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी भुगतान का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई है और साफ-सुथरे नोटों, सुरक्षित लॉजिस्टिक्स और ऐसे मुद्रा तंत्र के जरिए नकदी में लोगों का भरोसा बनाए रखना, जिस पर वे निर्भर कर सकें, मौद्रिक संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह ऐसा लक्ष्य है, जिसे सभी देशों के केंद्रीय बैंक साझा करते हैं, चाहे उनकी अर्थव्यवस्थाएं नकदी और डिजिटल भुगतान के किसी भी मिश्रण को अपनाएं।

ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई ने छह मूल्यवर्गों में हर साल 28 से 30 अरब बैंक नोटों का उत्पादन किया है और लगभग 21 अरब नोटों को हर साल चलन से हटा दिया है। फिलहाल भारत में 176 अरब बैंक नोट चलन में हैं। तुलना के लिए, पिछले साल के अंत में लगभग 56 अरब अमेरिकी डॉलर के नोट और 30 अरब यूरो के बैंक नोट चलन में थे।

मुर्मू ने कहा, तुलना के लिहाज से एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे आंकड़ों पर कुछ हद तक कम मूल्यवर्ग वाले नोटों की अधिक हिस्सेदारी का असर पड़ता है। इसका स्वाभाविक अर्थ है कि समान मूल्य के लेनदेन के लिए अधिक संख्या में नोट हाथ बदलते हैं। इसके बावजूद, यह मात्रा हमें हर दिन संभाले जाने वाले लॉजिस्टिक्स के पैमाने का अंदाजा देती है।

मुद्रा की टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई बैंक नोटों की उम्र बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रहा है। इनमें नोट के आधार पर सतही कोटिंग और कम मूल्यवर्ग के लिए पॉलिमर नोट शामिल हैं। नियामक नकदी चक्र के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके तहत दक्षता के लिए अपने वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाना और बैंक नोटों के ब्रिकेट्स के निपटान के तरीके में वैल्यू चेन में आगे बढ़ना शामिल है।

घरेलू पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए वितरकों को मिलेगी अतिरिक्त गैस

सरकार ने घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन बढ़ाने के लिए शहर गैस वितरकों को अतिरिक्त 200 मानक घन मीटर (एससीएम) सस्ती घरेलू गैस देने की घोषणा की है। इस प्रोत्साहन से एलपीजी से पीएनजी में बदलाव में तेजी आएगी और वितरकों का निवेश वापसी समय 10 साल से घटकर 3 साल हो जाएगा।

सरकार ने घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन दिया है। शहर गैस वितरकों को प्रत्येक नए बिल वाले घरेलू पीएनजी कनेक्शन पर 200 मानक घन मीटर (एससीएम) अतिरिक्त सस्ती घरेलू प्राकृतिक गैस मिलेगी। यह कदम कंपनियों को एलपीजी से पाइप गैस में बदलाव में तेजी लाने के लिए प्रेरित करेगा। यह प्रोत्साहन 1 सितंबर से प्रभावी होगा और प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के लिए निर्धारित सीमा से अधिक वृद्धिशील कनेक्शनों पर लागू होगा। यह योजना निष्क्रिय और बिना बिल वाले कनेक्शनों को चालू करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य नए क्षेत्रों में पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करना भी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

भारत में वर्तमान में लगभग 1.74 करोड़ घरेलू पीएनजी कनेक्शन मौजूद हैं। अतिरिक्त एपीएम (प्रशासित मूल्य तंत्र) गैस आवंटन से वितरक महंगी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की जगह सस्ती गैस का उपयोग कर पाएंगे। इससे उनकी कुल गैस-खरीद लागत में कमी आएगी। सरकार का अनुमान है कि इस बचत से घरेलू पीएनजी कनेक्शनों पर पूंजीगत व्यय की वापसी अवधि 10 साल से घटकर लगभग तीन साल हो जाएगी। यह वितरकों के लिए घरेलू कनेक्शनों का विस्तार करने हेतु एक मजबूत वित्तीय प्रोत्साहन है। यह योजना दो छह महीने की किस्तों में लागू की जाएगी।

क्यों जरूरी है पीएनजी का विस्तार?

पीएनजी को एलपीजी सिलेंडरों और पारंपरिक खाना पकाने के ईंधनों का एक स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक विकल्प माना जाता है। 2026 की शुरुआत में पश्चिम एशिया संकट के दौरान एलपीजी आपूर्ति में व्यवधान आया था। इससे सरकार को सिलेंडरों पर निर्भरता कम करने के तरीके खोजने पड़े। सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी थी। साथ ही, शहर गैस वितरकों को पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित किया। उपभोक्ताओं और कारोबारों को भी बदलाव के लिए प्रोत्साहन दिए गए।

सरकार ने पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मार्च से अब तक 5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन गैस से जुड़ चुके हैं। 5.7 लाख से अधिक ग्राहकों ने नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है। सरकार ने पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं से घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने को भी कहा है। पाइप गैस में बदलाव को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान भी शुरू किया गया है। सरकार ने गैस बुनियादी ढांचे के लिए नियामक बाधाओं को कम करने का भी प्रयास किया है। राज्यों को प्राकृतिक गैस पर वैट 5 फीसदी तक कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पीएनजी ड्राइव 2.0 और इसके लाभ क्या हैं?

एक राष्ट्रव्यापी पीएनजी अभियान 2.0 में जागरूकता अभियान शामिल हैं। इसमें एलपीजी का उपयोग करने वाली आवासीय सोसायटियों को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। घरों के लिए एलपीजी सिलिंडर सरेंडर करने की सुविधा भी दी गई है। नए पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन और ट्रैकिंग हेतु एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल भी विकसित हो रहा है। यह नवीनतम प्रोत्साहन योजना एपीएम और गैर-एपीएम गैस आवंटन दोनों को कवर करती है। पीएनजी पाइपलाइनों के माध्यम से लगातार आपूर्ति होती है, जो मीटर की गई खपत के अनुसार बिल की जाती है। यह सिलेंडरों को स्टोर करने की आवश्यकता कम कर घरेलू सुविधा और सुरक्षा बढ़ाती है। पीएनजी पारंपरिक ईंधनों की तुलना में स्वच्छ जलने वाला ईंधन भी है।

'ईरान पर होगी सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई': ट्रंप ने दी धमकी, मदद करने वाले देशों को चेताया, क्या बढ़ेगा तनाव

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त आर्थिक कार्रवाई की धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का सबसे बड़ा मौका दिया गया था। लेकिन उसने इसे गंवा दिया। ट्रंप ने कहा, इस्लामी गणराज्य ईरान को किसी समझौते के लिए मुझसे ज्यादा बड़ा मौका किसी ने नहीं दिया। दुख की बात है कि उन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। इसलिए आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई की घोषणा कर रहा हूं। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। उसकी वायु सेना नष्ट हो गई है। उसकी सैन्य फैक्टरियां मलबे में बदल गई हैं।

ईरान की मुद्रा बेकार हो गई है और देश बेहद कमजोर स्थिति में है।ईरान की मदद करने वाले देशों पर भी कार्रवाई?

ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद देगा, उसे भी बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसमें वित्तीय संस्थान, कारोबार, हवाई अड्डे और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने तेल की तस्करी, स्वैप लाइन, नकद लेनदेन, एक्सचेंज हाउस, जहाजों के पंजीकरण और ईरान की मदद करने वाली छिपी हुई (शेल) कंपनियों को तुरंत रोकने की बात कही।

सहयोगी देशों से अमेरिका के साथ आने की अपील

ट्रंप ने इसे ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक हमले का दिन बताया। उन्होंने अमेरिका के सहयोगी देशों से ईरान को अलग-थलग करने और उसके खतरे को खत्म करने में साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईरान इस समय बेहद कमजोर स्थिति में है। उन्होंने दावा किया कि ये ऐतिहासिक कदम ईरान को और दुनियाभर में आतंक फैलाने की उसकी क्षमता को बुरी तरह कमजोर कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा।

अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाया

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के पिछले हफ्ते इसी तरह बयान दिया था। बेसेंट ने कहा था कि अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिशें बढ़ाएगा। इस रणनीति में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी भी शामिल है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय 'ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी' नाम से प्रतिबंध अभियान भी चला रहा है। इसका मकसद लक्षित कार्रवाई के जरिये ईरान के पैसे जुटाने के स्रोतों को बंद करना है।

ईरान के खिलाफ युद्ध कब शुरू हुआ?

युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के हमलों के साथ हुई। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए।

कौन-कौन से देश ईरान के साथ?

रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने ईरान को सैन्य उपकरण और ड्रोन से जुड़ी तकनीक दी है। वहीं, चीन लगातार ईरान से तेल खरीद रहा है। चीन ने ईरान के साथ कारोबारी रिश्ते बनाए रखे हैं और उसे कूटनीतिक समर्थन भी दिया है। पाकिस्तान ने कूटनीति और बातचीत शुरू कराने की कोशिशों के जरिये ईरान का समर्थन किया है। हालांकि, उसने ईरान को सैन्य मदद नहीं दी है। रॉयटर्स के मुताबिक, ईरान को उसके सहयोगी हथियारबंद समूहों का भी समर्थन हासिल है। इनमें यमन के हूती और इराक में ईरान के साथ जुड़े लड़ाके शामिल हैं। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ 'बहुत कड़े प्रतिबंध' लगाने के विकल्प मौजूद हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ट्रंप ने दावा किया, अभी जलडमरूमध्य खुला है। बहुत सारी नावें वहां से गुजर रही हैं।

भारत पर क्या होगा असर?

भारत पर इसका असर तेल और गैस की कीमतों, नौवहन और महंगाई के रूप में पड़ सकता है, क्योंकि होर्मुज में तनाव बढ़ने से भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। साथ ही ईरान पर अमेरिकी दबाव बढ़ने से भारत के चाबहार बंदरगाह से जुड़ी योजनाओं पर भी असर पड़ने का खतरा है। चाबहार भारत के लिए ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का अहम रास्ता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध और मौजूदा संघर्ष पहले ही इसके कामकाज पर दबाव डाल रहे हैं।

पाकिस्तान सरकार के 25 मंत्रालय फर्जी! सीनेट समिति की सिफारिश– तुरंत हटाए मंत्री और अफसर

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान की सीनेट समिति ने शहबाज शरीफ के 25 मंत्रालयों को फर्जी करार दिया है। समिति ने सरकार से इन मंत्रालयों को तुरंत भंग करने की सिफारिश की है। जिन मंत्रालयों को भंग करने के लिए कहा गया है, उनमें रेल, पेट्रोलियम, जल संसाधन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मंत्रालय शामिल हैं। सीनेट समिति का कहना है कि इन मंत्रालयों के मंत्रियों और अधिकारियों को तुरंत हटाने की जरूरत है।

डॉन अखबार के मुताबिक सीनेट समिति का कहा है कि संविधान ने 1973 में जो प्रावधान लागू किए थे, उससे अलग जाकर सरकार ने मंत्रालयों का गठन किया है। यह राज्यों के अधिकारों का अवैध रूप से अतिक्रमण जैसा है।

1। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि रेल, पेट्रोलियम और जल जैसे विभाग राज्य और केंद्र के बीच का मसला है। केंद्र अकेले इस पर फैसला नहीं ले सकता है। इसके लिए पाकिस्तान में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का गठन किया गया है। इस काउंसिल में प्रधानमंत्री, 4 मुख्यमंत्री और 3 कैबिनेट मंत्री होते हैं।

2। पाकिस्तान के संघीय विधायी सूची के भाग-1 में कहा गया है कि केंद्र की सरकार सिर्फ 9 विभागों पर कंट्रोल करे। बाकी राज्यों के लिए छोड़ दें। केंद्र को सिर्फ इन 9 (रक्षा, विदेश मामले, वित्त, वाणिज्य, संचार, समुद्री मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कानून और न्याय और संसदीय मामले) का अधिकार दिया गया है।

3। संसद की सीनेट समिति का कहना है कि अतिरिक्त मंत्रालयों के संचालन के कारण हर साल 5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। यानी इन मंत्रालयों पर ये पैसे खर्च हो रहे हैं, जो गैर-जरूरी है।

इस वक्त पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वाह से लेकर बलूचिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक बवाल मचा है। हाल ही में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा कि यहां पर सिस्टम खत्म हो चुका है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के आम नागरिक पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं।

कश्मीर पर गोर का बयान पाक के अरमानों को झटका, वैश्विक तौर पर भारत की स्थिति मजबूत

वॉशिंगटन, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने और स्पेशल राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद से इस केंद्र शासित प्रदेश में आए ऐतिहासिक और जमीनी बदलावों पर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुहर लगती दिख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के एक ताजा बयान ने अलगाववादियों और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। श्रीनगर दौरे के दौरान गोर ने दो टूक कहा है कि "जम्मू-कश्मीर बहुत खूबसूरत है और भारत का एक अभिन्न हिस्सा है।"

गोर के इस बयान के सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में पाकिस्तान का प्रोपेगैंडा पूरी तरह बेनकाब हो गया है और उसका कश्मीर को लेकर देखा गया हर सपना टूटता नजर आ रहा है।

क्या कहा अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने?

श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने घाटी की खूबसूरती और वहां के हालात की तारीफ करते हुए कहा, "यहां आना बेहद सुखद है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं यहां पहली बार आया हूं। यह बेहद खूबसूरत जगह है। मैं यहां आकर और इस जगह को देखकर बेहद रोमांचित हूं। हमारी बहुत अच्छी बैठक हुई है।"

अमेरिकी राजदूत का यह बयान महज एक औपचारिक टिप्पणी भर नहीं है, बल्कि इसके गहरे कूटनीतिक मायने भी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी माने जाने वाले किसी शीर्ष राजनयिक का खुले तौर पर कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताना यह साबित करता है कि वैश्विक महाशक्तियां अब जम्मू-कश्मीर की जमीनी सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी हैं।

पाकिस्तान का स्टैंड और बौखलाहट

गोर का यह बयान पाकिस्तान के लिए बड़े झटके जैसा है। अमेरिका के इस रुख से पाकिस्तान का दशकों पुराना प्रोपेगैंडा धराशायी हो गया है। पाकिस्तान हमेशा से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को विवादित मुद्दा बताने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अमेरिका के इस स्पष्ट रुख ने उसके दावों की हवा निकाल दी है। इस्लामाबाद में खलबली मच गई। अमेरिकी राजदूत के इस बयान के तुरंत बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को तलब कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि यह पाकिस्तान की गहरी निराशा और बौखलाहट को साफ-साफ दिखाता है।

ग्लोबल डिप्लोमेसी और भारत की मजबूत स्थिति

इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस स्थिति को कैसे देखा जा रहा है? दुनिया अब मान चुकी है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में शांति, विकास और सामान्य स्थिति लौट आई है। यही वजह है कि अमेरिकी राजदूत ने घाटी में पर्यटन और अमेरिकी नागरिकों की यात्रा से जुड़े ट्रेवल एडवाइजरी की समीक्षा करने के संकेत भी दिए हैं।

भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी अहम मोड़ पर है। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में संबंध लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत का पलड़ा भारी होता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर अब दुनिया यह मानने लगी है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इस पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अब जगह कम होती जा रही है।

लद्दाख में जेन-जी महिला के बवाल का वीडियो वायरल: पूर्व अफसर नाराज, बोले- जवान सैलरी लेने से पहले टैक्स देते हैं

जम्मू, एजेंसी। लद्दाख के कारगिल स्थित मिनिमर्ग चेकपॉइंट पर एक महिला पर्यटक के हंगामे और उसके 'हम Gen Z हैं' वाले बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक नेताओं से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तक, कई लोगों ने महिला की टिप्पणियों की आलोचना की है। इस बीच सेना के कई पूर्व अधिकारियों ने सैनिकों के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था और सैनिकों के बलिदान पर सवाल उठाने से पहले तथ्यों और परिस्थितियों को समझना जरूरी है।

मिजोरम के राज्यपाल और सेना के पूर्व प्रमुख जनरल वीके सिंह (रिटायर्ड) ने गुरुवार को कहा कि किसी भी घटना की आलोचना तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि भावनाओं या बिना सोचे-समझे लगाए गए आरोपों के आधार पर। उन्होंने कहा कि मिनिमर्ग की घटना हमारे सैनिकों के साहस, बलिदान और सतर्कता की याद दिलाती है। ऐसे में सैनिकों को गलत तरीके से दोषी ठहराना या उनका अपमान करना उचित नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,'भारत के सशस्त्र बल हमारे देश और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के बीच खड़े हैं। मिनिमर्ग की घटना हमारे सैनिकों के साहस, बलिदान और सतर्कता की एक बड़ी याद दिलाती है।' हालात चाहे जो भी हों, हमारे सैनिकों को गलत तरीके से दोषी ठहराना या उनका अपमान करना गलत है। आलोचना तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि भावनाओं या बिना सोचे-समझे लगाए गए आरोपों पर। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो भारत की सेवा करते हैं और इसके लिए बलिदान देते हैं।

'हम Gen Z हैं... हम यह बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे'

वायरल वीडियो में महिला को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि लोग दूर-दूर से यात्रा करके आते हैं और अपनी यात्रा पर काफी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें 'यह सब' झेलना पड़ रहा है। वीडियो में वह चेकपॉइंट पर सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस करती नजर आती है। वह खुद को और अन्य लोगों को पर्यटक बताते हुए यह भी कहती सुनाई देती है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। इसी दौरान महिला को यह कहते हुए सुना जाता है,'हम Gen Z हैं... हम यह बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे।'

लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने महिला को दिया जवाब

उनकी यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो के बाद सामने आई, जिसमें कथित तौर पर एक महिला कारगिल, लद्दाख के मिनिमर्ग चेकपॉइंट पर सुरक्षाकर्मियों से बहस करती और हंगामा करती नजर आ रही है। वह उन कई पर्यटकों में शामिल थी, जिन्हें बैरिकेड वाले इलाके से आगे जाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। चिनार कॉर्प्स के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों (रिटायर्ड) ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस घटना पर प्रतिक्रिया दी और इलाके में तैनात सैनिकों का बचाव किया। महिला के कथित बयान,'हमारे टैक्स से उनकी सैलरी मिलती है', पर प्रतिक्रिया देते हुए ढिल्लों ने कहा कि सैनिक अपनी सैलरी मिलने से पहले ही टैक्स चुका देते हैं। सैनिक अपनी सैलरी मिलने से पहले ही अपना टैक्स चुका देते हैं। आप ऐसे इलाकों में छुट्टियां मनाने जा सकते हैं क्योंकि हमारे सैनिक दिन-रात इसकी सुरक्षा करते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान भी देनी पड़े। उन्होंने वीडियो में नजर आ रही महिला से यह भी अपील की कि वह अपने अधिकारों की मांग करने से पहले कानून का पालन करने वाली एक जिम्मेदार नागरिक बने। ढिल्लों ने लिखा,'आपकी भाषा आपकी अच्छी परवरिश और स्कूली शिक्षा की झलक होती है। हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करें। अधिकारों की मांग करने से पहले कानून का पालन करने वाला एक अच्छा नागरिक बनना सीखें। और आखिर में... 'जल्द ठीक हो जाइए।''

सोशल मीडिया पर भी महिला की टिप्पणियों की आलोचना

वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। राजनीतिक नेताओं से लेकर आम सोशल मीडिया यूजर्स तक, कई लोगों ने महिला की भाषा और सुरक्षाकर्मियों के साथ कथित तौर पर किए गए व्यवहार की आलोचना की।

लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने भी जताई नाराजगी

चिनार कॉर्प्स के एक अन्य पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ (रिटायर्ड) ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिखाई दे रही महिला की टिप्पणी सैनिकों के बलिदान का अपमान है। उन्होंने एक्स पर लिखा,'लद्दाख में, जहां ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा रहा था, एक महिला पर्यटक ने कहा, 'सेना की सैलरी हमारे टैक्स से दी जाती है।' मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह टिप्पणी सैनिकों के बलिदान का अपमान है। सेना के जवान भी टैक्स देते हैं। बॉर्डर एरिया होने के कारण लद्दाख में सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील परिस्थितियां होती हैं।'

आखिर वायरल वीडियो में हुआ क्या था?

बुधवार को कारगिल के मिनिमर्ग चेकपॉइंट पर अधिकारियों से बहस करती एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे लोगों में नाराजगी फैल गई। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह वीडियो 25 जुलाई का है। उस दिन जोजिला-गुमरी मार्ग पर रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के दौरे के कारण कुछ समय के लिए यातायात रोका गया था। रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को हवाई मार्ग से यात्रा करनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें हेलीकॉप्टर से गुमरी जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने सड़क मार्ग से कारगिल की यात्रा की।

18 साल की उम्र में आमिर खान ने किया था सनी देओल के साथ काम, बोले- 'तब वह बड़े स्टार थे'

आमिर खान और सनी देओल आज हिंदी सिनेमा के उन बड़े नामों में शामिल हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान है। दोनों ने अपने लंबे करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं और अब सालों बाद एक बार फिर पर्दे से जुड़े एक प्रोजेक्ट को लेकर साथ आए हैं। लेकिन इन दोनों कलाकारों का रिश्ता सिर्फ हाल के वर्षों का नहीं है। आमिर खान का सनी देओल से जुड़ाव उस समय का है, जब उन्होंने खुद बतौर अभिनेता बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा था। आमिर ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया और बताया कि वह महज 18 साल की उम्र में सनी देओल की फिल्मों में सहायक निर्देशक के तौर पर काम कर चुके थे। आमिर खान ने यह खुलासा क्विज-आधारित रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 18वें सीजन में किया। इस खास मौके पर आमिर के साथ सनी देओल और प्रीति जिंटा भी मौजूद थे।

शो में जब दर्शकों के साथ सवाल-जवाब चल रहा था, तब आमिर से सनी देओल के साथ पहली बार काम करने के बारे में पूछा गया। इसी सवाल के जवाब में आमिर ने अपने पुराने दिनों को याद किया और बताया कि सनी देओल के साथ उनका पहला काम उस समय हुआ था, जब वह सहायक निर्देशक थे।

आमिर ने कहा, 'जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तब मेरी शुरुआत एक सहायक निर्देशक के तौर पर हुई थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात सनी देओल से हुई। मेरे चाचा और मशहूर फिल्मकार नासिर हुसैन उस समय 'मंजिल मंजिल' और 'जबरदस्त' नाम की दो फिल्मों पर काम कर रहे थे। दोनों फिल्मों में सनी देओल मुख्य भूमिका में थे, और मैं इन फिल्मों में सहायक निर्देशक की जिम्मेदारी संभाल रहा था।'

आमिर ने आगे कहा, "मैंने करीब तीन साल तक सनी देओल के साथ सहायक के रूप में काम किया। उस वक्त मेरी उम्र महज 18 साल थी, जबकि सनी देओल इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुके थे और बड़े सितारे माने जाते थे। सनी जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने को लेकर मैं और मेरी टीम काफी उत्साहित रहती थी। मेरे लिए यह फिल्म इंडस्ट्री को करीब से समझने और सीखने का दौर था।"

आमिर ने जिस फिल्म का पहले जिक्र किया, वह फिल्म 'मंजिल मंजिल' साल 1984 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन नासिर हुसैन ने किया था। फिल्म में सनी देओल के साथ डिंपल कपाड़िया मुख्य भूमिका में थीं। डैनी डेंजोंगपा, प्रेम चोपड़ा और कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया था, जबकि इसके गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे। फिल्म के 'ओ मेरी जान' और 'लूट गए हम तो राहों में' जैसे गाने भी लोगों के बीच लोकप्रिय हुए थे।

वहीं आमिर ने नासिर हुसैन की एक और फिल्म 'जबरदस्त' का जिक्र किया था, वह फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी। इसमें सनी देओल के अलावा संजीव कुमार, जया प्रदा, राजीव कपूर, रति अग्निहोत्री, तनुजा और अमरीश पुरी जैसे कलाकार नजर आए थे। इसमें सनी देओल ने सुंदर कुमार का किरदार निभाया था, जो अपने परिवार और पिता के अतीत से जुड़े सच को जानने की कोशिश करता है।

अब सालों बाद आमिर खान और सनी देओल एक बार फिर साथ आए हैं। दोनों हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'बंटवारा 1947' से जुड़े। फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं और आमिर खान इसके निर्माता हैं। फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई है।

रवि तेजा की 'इरुमुदी' को मिला यू/ए सर्टिफिकेट, इस दिन से सिनेमाघरों में होगी रिलीज

साउथ सिनेमा के मशहूर निर्देशक शिव निर्वाण की आगामी तेलुगू फिल्म 'इरुमुदी' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने अब यू/ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज के लिए मंजूरी दे दी है। यह एक गहन पारिवारिक और भावनात्मक ड्रामा है, जिसमें एक्टर रवि तेजा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। मंगलवार को मैथ्री मूवी मेकर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने लीड रोल निभा रहे अभिनेता रवि तेजा की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, ₹फिल्म 'इरुमुदी' को यू/ए सर्टिफिकेट मिल गया है। इमोशनल फैमिली थ्रिलर के लिए टिकट बुक करने के लिए तैयार हो जाइए। 'इरुमुदी' 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।₹ शिव निर्वाण द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म में रवि तेजा, प्रिया भवानी शंकर, साई कुमार और बेबी नक्षत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। नवीन येरनेनी और वाई. रवि शंकर (मैत्री मूवी मेकर्स) मिलकर फिल्म के निर्माण कार्य में भूमिका अदा करते दिखेंगे।

फिल्म का शीर्षक 'इरुमुदी' भगवान अयप्पा की यात्रा और परंपरा से जुड़ा है। रवि तेजा इसमें एक आम और सहज पारिवारिक व्यक्ति के रूप में दिखाई देंगे, जिन्होंने अय्यप्पा की माला पहनी हुई है। फिल्म 21 अगस्त को रिलीज की जाएगी। हालांकि, पहले अफवाहें उड़ी थीं कि 'इरुमुदी' 21 अगस्त को रिलीज नहीं हो पाएगी, लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म का एक नया पोस्टर जारी करके इन अफवाहों पर विराम लगा दिया। पोस्टर में साफ लिखा था कि फिल्म तय तारीख 21 अगस्त को ही सिनेमाघरों में आएगी।

यह फिल्म रवि तेजा की 77वीं फिल्म है और इसलिए इसे

"इरुमुदी' टाइटल दिए जाने तक कुछ समय के लिए 'आरटी77' कहा जा रहा था।

मुख्य कलाकार रवि तेजा को फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने इसी साल जुलाई के दूसरे हफ्ते में फिल्म के लिए अपनी डबिंग शुरू की थी। इसी दौरान मेकर्स ने डबिंग स्टूडियो का एक वीडियो भी शेयर किया था। उस वीडियो में रवि तेजा डायलॉग बोलते दिखे - 'मेरी सिर्फ एक बेटी है और उसका नाम मनम्मा है।' इस वीडियो में बेबी नक्षत्रा और डायरेक्टर शिवा निर्वाण भी नजर आए।

सामंथा रुथ प्रभु के लिए अब 'कंप्रेशन सॉक्स' ही हैं फैशन, पैरों की सूजन के साथ साझा किया नया पोस्ट

अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपने पहले बच्चे के स्वागत की तैयारी में जुटी हुई हैं और इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बदलते फैशन को लेकर एक ऐसी पोस्ट साझा की, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। दरअसल, उन्होंने पैरों में पहने जाने वाले कंप्रेशन सॉक्स को ही अपना नया फैशन बता दिया। सामंथा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में उनके पैर सूजे हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कंप्रेशन सॉक्स पहने हुए है। इसी तस्वीर के साथ सामंथा ने बेहद छोटे लेकिन मजेदार अंदाज में लिखा, "अब जिसे मैं फैशन कहती हूं- कंप्रेशन सॉक्स।" दरअसल, आमतौर पर फैशन को कपड़ों, जूतों और गहनों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सामंथा ने अपनी मौजूदा स्थिति में आराम देने वाले सॉक्स को ही फैशन का नया नाम दे दिया। गर्भावस्था के दौरान पैरों और पंजों में सूजन की समस्या आम होती है। ऐसे में कंप्रेशन सॉक्स पैरों में आराम देने और ब्लड सुर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं।

दरअसल, सामंथा ने जून 2026 में अपनी प्रेग्नेंसी की आधिकारिक पुष्टि की थी। अभिनेत्री और उनके पति फिल्मकार राज निदिमोरु, अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। सामंथा ने यह खबर अपनी फिल्म 'मा इंटी बंगाराम' की सफलता के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में साझा की थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि वह कुछ समय के लिए अभिनय से दूरी बनाएंगी और मातृत्व अवकाश लेंगी।

मीडिया से बातचीत में सामंथा ने कहा था कि 'मा इंटी बंगाराम' के बाद उन्हें अपनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा और इसके बाद वह एक और फिल्म के साथ अपने फैंस के बीच वापस लौटेंगी।

कपल की बात करें, तो सामंथा और राज निदिमोरु ने 1 दिसंबर 2025 को शादी की थी। इस शादी में करीबी लोग ही शामिल हुए थे। दोनों की पहली मुलाकात 'द फैमिली मैन 2' के दौरान हुई थी। सामंथा ने इस चर्चित सीरीज में राजी नाम की दमदार भूमिका निभाई थी। शुरुआत में दोनों का रिश्ता पूरी तरह पेशेवर था।

'द फैमिली मैन 2' के बाद सामंथा और राज ने एक बार फिर साथ काम किया। दोनों 'सिटाडेलः हनी बनी' में साथ नजर आए, जो चर्चित वैश्विक 'सिटाडेल' सीरीज का भारतीय संस्करण था। सीरीज को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन इसके निर्माण के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की खबरें सामने आई थीं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालयः S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादकः प्रभात पांडेय सम्पर्कः 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com